● वर्ष-4
● अंक-147
रायपुर, गुरुवार
30 जनवरी 2025
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगछध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6» बेहद अलग है जूलॉजी में कॅरियर

कैबिनेट ने 16300 करोड़ रुपये के खनिज मिशन को मंजूरी दी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रीमंडल ने 16,300 करोड़ रुपये के खनिज मिशन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को इसका एलान किया। इसके साथ ही कैबिनेट ने सी श्रेणी के भारी गुड़ से उत्पादित इथेनॉल की एक्स-मिल कीमत 56.28 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 57.97 रुपये प्रति लीटर करने को भी मंजूरी दे दी है। सरकार की ओर से निर्धारित इथेनॉल की कीमतें 2022-23 इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (नवंबर-अक्तूबर) के बाद से नहीं बढ़ाई गई थी। गन्ने के रस, बी-हैवी गुड़ और सी-हैवी गुड़ से उत्पादित इथेनॉल की वर्तमान दरें क्रमश: 65.61 रुपये, 60.73 रुपये और 56.28 रुपये प्रति लीटर हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस वर्ष 31 अक्तूबर को समाप्त होने वाली 2024-25 अवधि के लिए इथेनॉल की कीमतों का एलान किया। सी श्रेणी के भारी गुड़ से प्राप्त इथेनॉल की एक्स-मिल कीमत 1.69 रुपये बढ़ाकर 57.97 रुपये प्रति लीटर करने को मंजूरी दी गई। बी श्रेणी के भारी गुड़ और गन्ना रस/चीनी/चीनी सिरप से उत्पादित इथेनॉल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। इनकी कीमतें क्रमश: 60.73 रुपये प्रति लीटर और 65.61 रुपये प्रति लीटर पर अपरिवर्तित रखी गईं।

इथेनॉल की कीमतें बढ़ाने का फैसला आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ली। इसकी जानकारी देते हुए सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2024-25 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के लिए इथेनॉल खरीद मूल्य में संशोधन को मंजूरी दी गई है। सरकार ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य भी 2030 से घटाकर इथेनॉल वर्ष 2025-26 कर दिया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है, इस दिशा में एक कदम उठाते हुए, तेल विपणन कंपनियों ने चालू ईएसवाई 2024-25 के दौरान 18 प्रतिशत इथेनॉल के मिश्रण की योजना बनाई है।

इस बीच, चीनी और इथेनॉल से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में तेजी दिखी है। ईआईडी-पैरी, श्री रेणुका शुगर्स, बलरामपुर चीनी मिल्स और त्रिवेणी इंजीनियरिंग के शेयरों में बीएसई सेंसेक्स पर 3.7फीसदी, 4.5 फीसदी, 2.5फीसदी और 2.3 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 0.62फीसदी की बढ़त दिखी।

पिनाका हथियार प्रणाली को लेकर बड़ा फैसला

केंद्र सरकार ने भारतीय सेना के पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली के लिए 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का गोला-बारूद खरीद को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक में यह मंजूरी दी गई। रक्षा सूत्रों ने बताया कि सीसीएस ने भारतीय सेना की जिस परियोजना को मंजूरी दी है उसके तहत अलग-अलग तरह के गोला बारूद खरीदे जाएंगे। कुछ हथियार सामग्री नागपुर स्थित सोलर इंडस्ट्रीज से और कुछ म्यूनिशन्स इंडिया लि. (एमआईएल) से खरीदे जाएंगे।

सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 13 जनवरी को अपने वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि पिनाका की दो अलग-अलग वैरायटी के हिसाब से दो अनुबंध किए जाने हैं। एक अनुबंध 5,700 करोड़ रुपये और दूसरा 4,500 करोड़ रुपये का है और सरकार से जल्द ही इन्हें मंजूरी मिलने की उम्मीद है। पिनाका पहले से ही निर्यात क्षेत्र में एक बड़ी सफलता की कहानी बन चुका है क्योंकि इसे आर्मेनिया खरीद चुका है जबकि फ्रांस सहित कई यूरोपीय देश इसमें रुचि दिखा रहे हैं।सीसीएस ने जिस हथियार प्रणाली के लिए मंजूरी दी है उसके रॉकेट की मारक क्षमता 45 किमी है। यह पाकिस्तान और चीन दोनों ही सीमाओं के लिए प्रभावी है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन पिनाका प्रणाली के लिए 120 किमी तक मारक क्षमता वाले रॉकेट विकसित करने के अंतिम चरण में है। सेना प्रमुख ने कहा था कि जैसे ही हमें पिनाका रॉकेट्स में लंबी रेंज मिलने लगेगी तो हम अन्य वैकल्पिक लंबी दूरी के हथियारों को छोड़कर इसी सिस्टम पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह रॉकेट सिस्टम कई वैरिएंट में उपलब्ध है और 75 किलोमीटर और उससे भी अधिक दूरी तक लक्ष्य को भेद सकता है। इससे पहले आर्मेनिया इसे खरीदने के लिए ऑर्डर दे चुका है और कई अन्य देश इसमें रुचि दिखा रहे हैं। पिनाका एमबीआरएल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने विकसित किया है और इसका उत्पादन सोलर इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टुब्रो, टाटा और ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड कंपनीज आदि मिलकर कर रहे हैं।

अखाड़ों ने सादगी से संगम में लगाई डुबकी

ईष्टदेव और धर्मध्वजा का कराया गया स्नान

महाकुंभ नगर (प्रयागराज)। संगम तट पर तड़के हुए हादसे को देखते हुए शैव, बैरागी एवं उदासीन अखाड़ों ने बेहद सादगी के साथ अमृत स्नान में हिस्सा लिया। तयशुदा समय से करीब पांच घंटे विलंब से आचार्य महामंडलेश्वर की अगुवाई में अखाड़ों के साधु-संतों ने छावनी से निकलकर त्रिवेणी में डुबकी लगाई। सबसे पहले अखाड़ों ने अपने ईष्टदेव को स्नान कराया। उसके बाद अखाड़े के निशान समेत धर्मध्वजा को भी वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्नान कराया। धर्म के जयकारों के बीच अखाड़ों के साधु-संतों ने नागा संन्यासियों के साथ पुण्य की डुबकी लगाई। मौनी अमावस्या पर मंगलवार तड़के करीब चार बजे से अखाड़ों का अमृत स्नान आरंभ होना था। करीब साढ़े तीन बजे महानिर्वाणी अखाड़े के साथ श्रीशंभू पंचायती अटल अखाड़ा के साधु-संत एवं नागा संन्यासी सज-धजकर स्नान करने के लिए निकल पड़े। करीब पांच सौ मीटर दूर पहुंचने पर अखाड़ा सचिव श्रीमहंत जमुनापुरी को प्रशासन ने संगम के पास हादसे की सूचना दी। इसके बाद अखाड़ा पदाधिकारियों ने लौटने का फैसला कर लिया। श्रीपंचायती निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा ने भी अपनी-अपनी छावनी में चल रही स्नान की तैयारियां रोक दीं।अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने अन्य पदाधिकारियों को भी छावनी में बुला लिया। मेला प्रशासन के आला-अफसर भी पहुंच गए। कई घंटे चली मंत्रणा के बाद अखाड़े सादगी से स्नान पर राजी हो गए। इसके बाद अखाड़ों के क्रम से मुताबिक वरिष्ठ पदाधिकारियों समेत साधु-संतों ने बिना ढोल बाजे एवं शाही सवारी के ही त्रिवेणी में डुबकी लगाई।सुबह करीब साढ़े दस बजे महानिर्वाणी अखाड़े के बाद श्रीनिरंजनी अखाड़े से आचार्य पीठाधीश्वर कैलाशानंद गिरि की अगुवाई में अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी, सचिव श्रीमहंत रामरतन, ओमकार गिरि, राधे गिरि समेत अन्य साधु-संतों ने नागा संन्यासियों के साथ त्रिवेणी में डुबकी लगाई। आनंद अखाड़े ने भी आचार्य पीठाधीश्वर बालकानंद गिरि की अगुवाई में अमृत स्नान किया। तीसरे क्रम में जूना अखाड़े के साथ अग्नि एवं आवाहन अखाड़े के साधु-संत भगवान दत्तात्रेय के जयकारे लगाते हुए पहुंचे। आचार्य पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरि की अगुवाई में वैदिक रीति से अखाड़े की धार्मिक क्रियाएं कराई गईं।

हादसे की होगी न्यायिक जांच

मुख्यमंत्री ने हादसे की न्यायिक जांच के आदेश देते हुए तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया। इस आयोग के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश हर्ष कुमार होंगे, जबकि पूर्व डीजी वी.के. गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस डी.के. सिंह को आयोग में शामिल किया गया है। यह आयोग एक समय सीमा के अंदर अपनी रिपोर्ट देगा। पुलिस भी मामले की जांच करेगी और हादसे के कारणों की गहराई से पड़ताल की जाएगी। यही नहीं, गुरुवार को मुख्य सचिव और डीजीपी भी प्रयागराज जाकर घटना की समीक्षा करेंगे।

मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख का मुआवजा : मुख्यमंत्री ने घटना पर गहरी चिंता जताते हुए कहा, फ्रप्रशासन ने कई दौर की समीक्षा बैठकें की थीं, फिर भी यह हादसा कैसे हुआ? इसकी गहन जांच होगी।फ्र सरकार ने मृतकों के परिवारों को ?25-25 लाख की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव और डीजीपी को गुरुवार को घटनास्थल का दौरा कर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। वे हालात का जायजा लेंगे और रिपोर्ट सौंपेंगे।

बीटिंग रिट्रीट के साथ हुआ गणतंत्र दिवस समारोह का समापन

नई दिल्ली। रायसीना हिल्स पर डूबते सूरज के साथ ही हर साल की तरह इस बार भी बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम पूर्ण हुआ। बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान विजय चौक पर पैर थिरकाने वाली धुनों ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बीटिंग द रिट्रीट के साथ ही गणतंत्र दिवस का औपचारिक समापन हो गया। बीटिंग द रिट्रीट के दौरान तीनों सेनाओं के साथ ही सीएपीएफ के बैंड ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य लोगों के सामने 30 फुट टैपिंग धुनें बजाईं। इनमें %कदम कदम बढ़ाए जा% और %ऐ वतन तेरे लिए% से लेकर %गंगा जमुना% और %भारत के जवान% तक शामिल थीं।

इस समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पारंपरिक रूप से खुली सोने की परत वाली बग्घी में सवार होकर विजय चौक पहुंची। उनके अलावा, बीटिंग रिट्रीट समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेता मौजूद रहे। नेताओं के अलावा बड़ी संख्या में जनता ने भी बीटिंग द रिट्रीट देखी।

प्रमुख समाचार

घरेलू कामगारों के अधिकारों के लिए बने कानून: सुप्रीम कोर्ट

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से घरेलू कामगारों की चिंताओं और अधिकारों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए एक कानूनी ढांचा पेश करने की आवश्यकता पर विचार करने को कहा। शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार आज अदालत द्वारा गठित की जाने वाली समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद कानून पारित करने पर विचार कर सकती है। घरेलू कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, अदालत ने श्रम और रोजगार मंत्रालय को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय और कानून और न्याय मंत्रालय के समन्वय से संयुक्त रूप से गठन करने का निर्देश दिया है। विषय विशेषज्ञों वाली समिति घरेलू कामगारों के अधिकारों के लाभ, सुरक्षा और विनियमन के लिए एक कानूनी ढांचे की सिफारिश करने की वांछनीयता का आकलन करेगी। विशेषज्ञ समिति की संरचना भारत सरकार और उसके संबंधित मंत्रालयों के विवेक पर छोड़ दी गई है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि अगर समिति छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देती है तो इसकी सराहना की जाएगी।

केजरीवाल केवल झूठे वादे करते हैं: राहुल गांधी

नईदिल्ली। दिल्ली चुनाव को लेकर बवाना में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि पहले अरविंद केजरीवाल छोटी कार में शहर में घूमते थे, बिजली के खंभों पर चढ़ते थे। उन्होंने कहा था कि मैं स्वच्छ राजनीति लाऊंगा। उसके बाद दिल्ली में सबसे बड़ा घोटाला--करोड़ों रुपये का शराब घोटाला, उनकी पार्टी ने, उनके लोगों ने किया। उन्होंने कॉरपोरेट सरकार चलाई है। पांच साल पहले, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वह यमुना नदी में स्नान करेंगे और यमुना नदी का पानी पीएंगे। पांच साल हो गये, आज तक केजरीवाल जी ने यमुना का पानी नहीं पिया। राहुल कहा साफ तौर पर कहा कि लोगों को गंदा पानी पीना पड़ता है लेकिन केजरीवाल जी शीशमहल में रहते हैं। वह करोड़ों रुपए के घर में रहते हैं। वह साफ पानी पीते हैं और आपको गलत बयान देते हैं।% राहुल ने कहा कि हम रोजगार, विकास और प्रगति की बात करते हैं। आपको याद होगा कि शीला दीक्षित के शासनकाल में दिल्ली में सड़कें बनी थीं। विकास हुआ। हमने झूठे वादे नहीं किये। केजरीवाल जी और मोदी जी दोनों झूठे वादे करते हैं।

अखिलेश को नहीं करना चाहिए केजरीवाल का समर्थन:बृजभूषण

नईदिल्ली। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। बृजभूषण शरण सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल एक धूर्त आदमी हैं। उन्होंने कहा कि मेरी राय में, अखिलेश यादव को उनका समर्थन नहीं करना चाहिए था। उन्होंने दावा किया कि इस बार बीजेपी बहुत अच्छी तरह से लड़ रही है। दिल्ली के मूल नागरिक अरविंद केजरीवाल के झूठ से तंग आ चुके हैं, अब क्योंकि वह कहते हैं कि हरियाणा सरकार ने यमुना में खतरनाक सामग्री छोड़ी है, यह महज एक दोष है जैसा कि उन्होंने पिछले 10 वर्षों में किया था। बृजभूषण शरण सिंह ने केजरीवाल से सवाल करते हुए कहा कि उन्होंने यमुना के लिए क्या किया, दिल्ली में प्रदूषण, बेरोजगारी, सड़कें, बुनियादी ढांचा, या यहां तक ??कि कोरोना काल में भी क्या किया?इससे पहले बृजभूषण सिंह ने कहा कि 10 साल के शासन में अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ आरोप लगाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मैंने आज तक इससे बड़ा राजनीतिक फराडिया नहीं देखा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने पिछले साल में कुछ काम नहीं किया।

सीएजी रिपोर्ट को लेकर आप सरकार पर हमलावर कांग्रेस

नईदिल्ली। कांग्रेस ने बुधवार को 14 विवादास्पद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) रिपोर्ट पेश करने को लेकर आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की आलोचना की। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल अपनी सरकारके खिलाफ सीएजी रिपोर्ट के फर्जी ड्राफ्ट लेकर आते थे लेकिन अब चुप हैं। पवन खेड़ा ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय राजधानी में आप सरकार के प्रदर्शन पर सीएजी रिपोर्ट पर बहस की चुनौती भी दी। क्या उन्होंने अपनी छ्रत्त रिपोर्ट पढ़ी है? वह हमारे (कांग्रेस) खिलाफ फर्जी सीएजी रिपोर्ट लेकर पूरे देश में घूमते थे। अब जब उनके खिलाफ इतनी सारी छ्रत्त रिपोर्टें आ गई हैं तो उनका मुंह क्यों बंद है? कांग्रेस नेता ने कहा कि हिम्मत है तो आएं और अपनी सीएजी रिपोर्ट पर बहस करें (अगर उनमें हिम्मत है तो उन्हें हमारे साथ सीएजी रिपोर्ट पर बहस करनी चाहिए। केजरीवाल छोटी कार में आते थे और नई तरह की राजनीति का वादा करते थे। अगर आपको याद हो तो वह भ्रष्टाचार के खिलाफ बिजली के खंभे पर चढ़ गए थे।

तहव्वुर राणा को भारत लाने की तैयारी शुरू

नईदिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा, जो भारत में वांछित है, के प्रत्यर्पण की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा कर सकती है। सूत्रों ने बताया कि भारतीय एजेंसियां लगातार अमेरिकी एजेंसियों के संपर्क में हैं और एक टीम जल्द ही अमेरिका के लिए रवाना हो सकती है। यह कदम अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद आया है, जिसमें राणा द्वारा भारत में उसके प्रत्यर्पण को चुनौती देने वाली समीक्षा याचिका खारिज कर दी गई थी। इस निर्णय ने एक महत्वपूर्ण कानूनी बाधा को दूर कर दिया है, जिससे भारतीय अधिकारियों को उसे न्याय दिलाने की प्रक्रिया में तेजी लाने की अनुमति मिल गई है। एएनआई ने बताया कि महानिरीक्षक और उपमहानिरीक्षक रैंक के अधिकारियों की एक टीम इस महीने के अंत तक अमेरिका का दौरा कर सकती है और इसका विवरण गृह मंत्रालय के साथ-साथ विदेश मंत्रालय के साथ भी साझा किया गया है। 13 नवंबर को राणा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सर्टिओरीरी की रिट के लिए याचिका दायर की थी।

इसरो का 100वां लॉन्च सफल

भारत ताकतवर हुआ, तकनीक पर निर्भरता खत्म करने की तरफ बढ़े

कीर्तिवर्धन मिश्र

इसरो ने बुधवार सुबह 6.23 बजे अपना 100वां मिशन लॉन्च किया। इसके तहत श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से जीएसएलवी-एफ15 के जरिए 2250 किलोग्राम की नैविगेशन सैटेलाइट एनवीएस-02 को भेजा गया। नैविगेशन उपग्रह एनवीएस-2 नैविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन यानी नाविक श्रृंखला का दूसरा उपग्रह है। इस श्रृंखला में कुल पांच सैटेलाइट भेजी जानी हैं।

इससे पहले एनवीएस-01, जो दूसरी पीढ़ी का पहला सैटेलाइट था, 29 मई 2023 को जीएसएलवी-एफ12 के जरिए लॉन्च किया गया था। जबकि, एनवीएस-02, एनवीएस सीरीज का दूसरा सैटेलाइट है। इसमें एल1, एल5 और एस बैंड में नेविगेशन पेलोड के साथ-साथ सी-बैंड में रेंजिंग पेलोड भी लगाया गया है, जैसा कि इसकी पहली पीढ़ी की सैटेलाइट एनवीएस-01 में था।

मिशन में क्या-क्या खास

अंतरिक्ष मामलों के विशेषज्ञों के मुताबिक, एनवीएस-02 के जरिए भारत अपने नाविक सिस्टम को मजबूत करेगा। इसरो का यह उपग्रह पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से देश में ही बना है। इसे यूआर सैटेलाइट सेंटर (यूआरएससी) में डिजाइन, विकसित और तैयार किया गया है। नवंबर-दिसंबर 2024 के बीच इस सैटेलाइट की टेस्टिंग की गई, जिसमें इसकी हर परिस्थिति का सामना करने की काबिलियत को परखा गया।

इसमें भारत के सटीक समय की जानकारी देने के लिए एक परमाणु घड़ी भी लगाई गई है, जिसे रूबिडियम एटॉमिक फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड (आरएएफएस) भी कहा जाता है।

जिस नाविक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इस उपग्रह को लॉन्च किया गया है, उसके जरिए भारत को कई क्षेत्रों में स्वतंत्र और स्वायत्त बनाने के लिए की गई है। मसलन भारत में अभी नक्शों से लेकर मोबाइल-कंप्यूटर पर समय तक के लिए लोगों को विदेशी तकनीक पर निर्भर रहना पड़ता है।

भारत में नक्शे पर किसी भी जगह या किसी चीज की सटीक स्थिति बताने, गति और डिजिटल डिवाइसेज पर सही समय बताने के लिए देश अब तक अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) तकनीक या रूस के ग्लोनास सिस्टम पर निर्भर है।

इतना ही नहीं दुनिया की अधिकतर महाशक्तियों ने सैटेलाइट नैविगेशन सिस्टम के क्षेत्र में स्वायतत्ता हासिल करने के लिए अपनी खुद की प्रणालिया बना ली हैं। अमेरिका और रूस के अलावा चीन ने अपना बेइडू नैविगेशन सिस्टम स्थापित किया है। इसके अलावा यूरोपीय संघ अपने क्षेत्र में नैविगेशन सेवाओं के लिए गैलिलियो सिस्टम का इस्तेमाल करता है।

अपना नैविगेशन सिस्टम

भारत की तरफ से अपना नैविगेशन सिस्टम- नाविक बनाने की एक अहम वजह कूटनीतिक स्तर पर स्वतंत्रता और स्वायत्तता हासिल करना है। दरअसल, किसी तनाव की स्थिति में विदेशी ताकतें अपने सैटेलाइट नैविगेशन सिस्टम के इस्तेमाल को दूसरे देशों के लिए बंद कर सकती हैं।

भारत के साथ 1999 में यह हो भी चुका है। कारगिल युद्ध के दौरान भारत ने अमेरिका से अपने ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) के जरिए ट्रैकिंग की सुविधा कारगिल में मुहैया कराने की मांग की थी। इसके जरिए भारत आतंकियों की सही स्थिति जानने की कोशिश में था। हालांकि, तब अमेरिका ने इस मांग को नकार दिया था। तब भारत को पहली बार अपने स्वदेशी सैटेलाइट नैविगेशन सिस्टम की जरूरत महसूस हुई, जो देश के नक्शे पर सही स्थिति, सही समय और गति बताने का काम करे। इसी कड़ी में 2006 में भारत ने स्वदेशी प्रोजेक्ट नाविक की शुरुआत की।भारत की तरफ से इस प्रोजेक्ट में सैटेलाइट लॉन्च करने की प्रक्रिया 2013 से ही शुरू कर दी गई थी। तब भारत ने आईआरएनएसएस वर्ग की सैटेलाइट लॉन्च की थीं। 2013 से 2018 तक इस रेंज की कुल नौ सैटेलाइट लॉन्च की गईं। भारत ने इसके बाद एनवीएस सीरीज की सैटेलाइट्स लॉन्च करना शुरू किया।

इन सैटेलाइट का मकसद आईआरएनएसएस सैटेलाइट प्रणालियों को और मजबूत करना है। एनवीएस-2 इस श्रेणी की सबसे नई सैटेलाइट है। इस प्रोजेक्ट के तहत अब तक कुल 11 सैटेलाइट (नौ ढ्ढक्रहृस्स्‌ सैटेलाइट और दो हृङ्क्रस्‌ सैटेलाइट) लॉन्च की गई हैं, जिनमें से एक का लॉन्च नाकाम रहा था। वहीं 10 सैटेलाइट अपनी कक्षाओं में हैं। इनमें से 6 सैटेलाइट ठीक ढंग से काम कर रही हैं। वहीं चार सैटेलाइट शॉर्ट मैसेज ब्रॉडकास्ट सेवाओं में काम आ रही हैं। भारत का यह सैटेलाइट नैविगेशन सिस्टम फिलहाल सैन्य क्षेत्रों में इस्तेमाल के लिए ही सीमित रखा गया है। यानी इस सिस्टम को कूटनीतिक क्षेत्र में प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि, एनवीएस सैटेलाइट्स के कक्षा में स्थापित होने के बाद नाविक सिस्टम और ज्यादा मजबूत होकर उभरेगा। एनवीएस वर्ग की पांच सैटेलाइट्स की स्थापना के बाद नाविक सैटेलाइट नैविगेशन सिस्टम को नागरिकों को भी मुहैया कराए जाने की संभावना है।

चिरमिरी में नामांकन दाखिले के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के महापौर पद के प्रत्याशी रामनरेश राय ने मंगलवार को हजारों समर्थकों के साथ भव्य रैली निकालकर नगर पालिक निगम चिरमिरी में अपना नामांकन दाखिल किया। इस रैली में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और भाजपा जिला अध्यक्ष चंपा देवी पावले भी शामिल हुईं।

रामनरेश राय की रैली सीताकुंड के बड़ा बाजार से नगर पालिका कार्यालय तक पहुंची। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, चिरमिरी का विकास भाजपा के हाथों में सुरक्षित है। डबल इंजन सरकार ने प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। हमसे पहले की कांग्रेस सरकार ने जनता को सिर्फ धोखा दिया।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कांग्रेस सरकार के दौरान नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम पर था। हमने सेनेटाइजर घोटाला, सड़क निर्माण घोटाला और कई अन्य भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया है। भाजपा के महापौर बनने पर इन सभी मामलों की जांच कराई जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। मंत्री जायसवाल ने पार्टी के विजन को साझा करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार चिरमिरी में नए स्कूल, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और रेलवे कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देगी।

वहीं भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस महापौर प्रत्याशी डॉ। विनय जायसवाल ने कहा, भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। यदि भाजपा के पास सबूत हैं, तो पिछले पांच साल में इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कांग्रेस सरकार ने क्षेत्र में विकास कार्य किए हैं, जिसे जनता देख रही है।

डॉ. जायसवाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा की सरकार ने केवल खोखले वादे किए। हमारी सरकार ने किसानों को कर्जमाफी, मजदूरों के लिए योजनाएं और नगरीय निकायों में विकास कार्य सुनिश्चित किए। भाजपा के नेताओं की रैली केवल दिखावा है।

चिरमिरी में राजनीतिक लड़ाई मुख्य रूप से विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर केंद्रित है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने एक दूसरे पर तीखे आरोप लगाए हैं। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के कार्यकाल में नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। वहीं कांग्रेस का दावा है कि भाजपा केवल वादों की राजनीति कर रही है।

इस बार चिरमिरी नगर पालिका निगम चुनाव में महापौर पद के लिए भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। जनता के बीच दोनों पार्टियों की नीतियों और पिछले कार्यकाल के प्रदर्शन को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

जशपुर में भाजपा ने रैली निकाली और प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल कराया

जशपुर। नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामाकंन के अंतिम दिन शहर में गहमागहमी का माहौल देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के साथ नामांकन रैली का आयोजन कर शहर में अपने पक्ष में चुनावी माहौल तैयार करने का प्रयास किया। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी अंतिम दिन नामांकन जमा करने के लिए भाग दौड़ करते नजर आए।

भाजपा की नामांकन रैली की शुरुआत शहर के बीएस मार्केट में स्थित मां काली मंदिर से हुई। यहां विधायक रायमुनि भगत,वरिष्ठ भाजपा नेता कृष्ण कुमार राय और चुनाव प्रभारी रामकिशुन सिंह के नेतृत्व में गाजे-बाजे के साथ रैली कलेक्टर कार्यालय के लिए रवाना हुई। नामांकन रैली बालाजी मंदिर,जय स्तंभ चौक,सिटी कोतवाली,रणजीता स्टेडियम होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची। यहां भाजपा के प्रत्याशियों ने अपर कलेक्टर के पास पर्चा जमा किया।

मीडिया से चर्चा करते हुए विधायक रायमुनि भगत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे को लेकर नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदाताओं के बीच जाएगी। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद बीते एक साल के दौरान शहर का जो विकास हुआ है, वह सबको दिखाई दे रहा है।यही भाजपा का मुख्य चुनावी मुद्दा होगा।

वरिष्ठ भाजपा नेता कृष्ण कुमार राय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के एक साल के कार्यकाल के दौरान हुए कार्य और शहर के विकास के लिए आने वाले समय में होने वाले कार्यों को लेकर भाजपा कार्यकर्ता मतदाताओं तक पहुंचेंगे।

भाजपा से नगरपालिका के लिए अध्यक्ष प्रत्याशी अरविंद भगत ने बताया कि इस वक्त चुनाव में जीत के लिए सकारात्मक सोच के साथ वह मैदान में उतर रहे हैं। भाजपा के 13 माह में जो विकास की गति यहां बढ़ी है, उस गति को तेज करने वह अपना सर्वस्व लगा देंगे। जनता की सेवा के साथ साथ उनकी समस्याओं का निराकरण करना प्रथम कर्तव्य रहेगा।

वहीं कांग्रेस ने भाजपा के नगर सरकार के कार्यकाल के दौरान विकास कार्यो में हुई गड़बड़ी और 2014 से 19 तक अध्यक्ष रहे हीरू राम निकुंज के कार्यकाल में हुए विकास कार्य को लेकर मतदाताओं से समर्थन मांगने की तैयारी की है। निकुंज ने कहा कि इन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस कार्यकर्ता मतदाताओं से समर्थन मांगेंगे।

ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सहस्त्रांशु पाठक ने कहा कि विकास के नाम पर भाजपा ने बीते एक साल के दौरान सिर्फ शहर में पूर्व से बने हुए सीसी रोड पर डामर लगाने का काम किया है। प्रदेश सचिव अजय गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस नगरपालिका के सभी 20 वार्डों में मजबूती से चुनाव लड़ेगी।

लेडिस टेलर को जांजगीर नैला नगर पालिका अध्यक्ष का टिकट

जांजगीर चांपा। मशीन पर बैठकर सिलाई कर रही इस महिला का नाम चित्ररेखा गढ़ेवाल है। कहने को तो ये एक आम महिला है, लेकिन छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के दौरान इस महिला को खास जिम्मेदारी मिली है। भारतीय जनता पार्टी ने जांजगीर नैला नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए चित्ररेखा गढ़ेवाल को प्रत्याशी बनाया है।

जांजगीर नैला नगर पालिका सीट अनुसूचित जाति महिला वर्ग के लिए आरक्षित सीट है। इस सीट पर भाजपा ने वार्ड 25 में रहकर टेलरिंग काम करने वाली महिला चित्ररेखा गढ़ेवाल को अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में उतारा है।

चित्ररेखा गढ़ेवाल ने बताया मुझे विश्वास था कि पार्टी अध्यक्ष पद के लिए टिकट जरूर देगी। मैडम ने कहा कि चुनाव के दौरान लेडिस टेलर का काम नहीं करना, जीतने के बाद फिर से सिलाई का काम करुंगी।

चित्ररेखा ने 8वीं तक की पढ़ाई की है। घर के कामों के साथ टेलरिंग का काम करती है। घर में कपड़ों की सिलाई के साथ ही आसपास की महिलाओं और युवतियों को सिलाई का काम भी सिखाती है। इन सबसे चित्ररेखा की महीने में लगभग 3 से 4 हजार रुपये की कमाई हो जाती है। घर में एक छोटी सी दुकान भी है। पिछले 20 साल से वह बीजेपी से जुड़ी है। नगरीय निकाय चुनाव में अचानक इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने से वह काफी खुश है और जीत कर अपने क्षेत्र की हर समस्या दूर करने का दावा कर रही है।

चित्ररेखा गढ़ेवाल ने बताया रोड में गाय बैठी रहती है। नालियों में सफाई नहीं होती। कई क्षेत्रों में बिजली नहीं है। आवास की भी लोगों को परेशानी है।

चित्ररेखा जनसेवा की भावना लेकर पहले वार्ड पार्षद भी चुनी गई थी। पार्षद के बाद बीजेपी महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष रही और अभी महिला मोर्चा की सोशल मिडिया प्रभारी है। इस बार बीजेपी ने चित्ररेखा को अध्यक्ष पद के लिए उतारा है। नगरीय निकाय चुनाव में अचानक इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने से चित्ररेखा काफी खुश है और जीत कर अपने क्षेत्र की हर समस्या दूर करने का दावा कर रही है। लेकिन इन सबमें खास बात ये है कि आजीविका चलाने के लिए जिस टेलरिंग के काम को सीखा उसे आज भी कर रही है।

72 अधूरे आवासों को पूर्ण बताकर 86 लाख रुपये गबन

■ **दो रोजगार सहायक बर्खास्त, छह लोगों के खिलाफ एफआईआर**

कोरबा। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटला का मामला सामने आया है। 72 अधूरे आवासों को पूर्ण बताकर 86 लाख रुपये का गबन किया गया है। मामले में दो रोजगार सहायक को बर्खास्त किया गया है। वहीं अन्य रोजगार सहायक और ठेकेदार के खिलाफ थाना में एफआईआर दर्ज किया गया है। पूरा मामला कोरबा जिले का है।

प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि गबन करने के मामले में कोरबा जिले में छह लोगों के खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई की गई है, जिसमें तीन ठेकेदार, दो पूर्व रोजगार सहायक और एक पूर्व आवास मित्र शामिल है। कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत के निर्देश पर हुई इस कार्यवाही के चलते पूर्व रोजगार सहायक प्रकाश चौहान और किरण महंत को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

वहीं ठेकेदार मेघनाथ विश्वकर्मा, राजाराम चौहान ग्राम सिमकेंदा, लखनलाल बैगा ग्राम श्यांग, रोजगार सहायक ग्राम श्यांग प्रकाश चौहान और ग्राम सोल्वा के किरण महंत, पूर्व आवास मित्र चंद्रशेखर मँझवार, ग्राम करूमौहा के खिलाफ पुलिस थाना श्यांग कोरबा में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

जिला प्रशासन कोरबा को यह शिकायत मिली थी कि जनपद पंचायत कोरबा अंतर्गत ग्राम पंचायत श्यांग, सिमकेदा, एवं सोल्वा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 72 हितग्राहियों के आवास आधे अधूरे हैं। आवास बने ही नहीं और 86 लाख रुपए निकाल लिए गए। शिकायत के संबंध में जिला स्तरीय जांच समिति गठित कर जांच कराई गई थी।

जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त तीनों ग्रामों में स्वीकृत 72 आवासों के लिए ठेकेदार राजाराम, मेघनाथ विश्वकर्मा, लखनलाल बैगा और तत्कालीन रोजगार सहायक प्रकाश चौहान,किरण महंत, तत्कालीन आवास मित्र चंद्रशेखर मँझवार के द्वारा आवास की राशि निकाल ली गई है, जिसके कारण आवास निर्माण का कार्य अधूरा है। तत्कालीन विकासखंड समन्वयक लम्बोदर कौशिक, कलेश्वर चौहान तथा तकनीकी सहायक नरेंद्र साहू द्वारा भी बिना भौतिक सत्यापन के आवास पूर्ण होने का जिओ टैग कर पूर्ण भुगतान कराया गया।

सीईओ जिला पंचायत ने बताया कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की जा रही है। जनपद पंचायत सीईओ देवानंद श्रीवास के पत्र के अनुसार विकासखंड समन्वयक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जनपद पंचायत कोरबा के द्वारा उक्त छह लोगों पर पुलिस थाना श्यांग कोरबा में शासकीय राशि के गबन की प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

मेडिकल कॉलेज के डीन खिलाफ सुरक्षाकर्मियों ने खोला मोर्चा

कोरबा। कोरबा में जिला अस्पताल के मेडिकल कॉलेज में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने डीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुरक्षाकर्मियों का आरोप है कि जिला मेडिकल कॉलेज के डीन केके सहारे ने नाइट ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मी दिलीप कुमार को सरेआम थप्पड़ मार दिया है।

इस घटना के बाद सभी सुरक्षा कर्मियों ने काम बंद कर दिया है। सभी सुरक्षाकर्मी जिला मेडिकल कॉलेज परिसर पर आंदोलन पर डटे हुए हैं। सुरक्षाकर्मियों की मांग है कि डीन सार्वजनिक रूप से उससे माफी मांगे नहीं तो वह काम पर नहीं जाएंगे और इसकी शिकायत पुलिस से करेंगे। हालांकि डीन केके सहारे ने कहा कि सुरक्षाकर्मियों से बातचीत कर उन्हें मना लिया गया है और सभी काम पर वापस लौट गए हैं।

ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी दिलीप ने बताया कि वह ड्यूटी पर था। इस दौरान काफी भीड़भाड़ थी और ड्यूटी डॉक्टर शराब के नशे में था, जिसके चलते मरीज परेशान थे। पुलिसकर्मी जायजा लेने आए हुए थे। इस सूचना पर जिला मेडिकल कॉलेज के डीन अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और उन्हें यह कहते हुए थप्पड़ मारा की इतना भीड़ क्यों लगाए हुए हो। सुरक्षाकर्मी ने बताया कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर गुनेश्वर सिह कंवर शराब के नशे में धुत था और इलाज नहीं कर रहा था। जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। तब जाकर यह स्थिति निर्मित हुई। डीन मौके पर पहुंचे और गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। डीन केके सहारे ने बताया कि रात के वक्त सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे जहां ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मी काम के दौरान लापरवाही बरत रहा था तो उसे डांट फटकार लगाई गई। वहीं डॉक्टर की भी जांच कराई जा रही है, रिपोर्ट आना बाकी है सुरक्षाकर्मियों से बातचीत कर उन्हें मना लिया गया है और सभी काम पर वापस लौट गए हैं।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

'मिस छत्तीसगढ़' ने चुनावी रण में लगाया ग्लैमर का तड़का

जांजगीर। प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अलग-अलग कार्य क्षेत्र में परांगत प्रत्याशी दांव आजमा रहे हैं। कहीं गुपचुप वाली, तो कहीं चाय वाला, तो कहीं लेडिस टेलर के चुनाव मैदान उतरने से मुकाबला रोचक और रोमांचक हो चुका है। ऐसे में अकलतरा नगर पालिका में अध्यक्ष पद के चुनाव में 'मिस छत्तीसगढ़' की एंट्री से ग्लैमर का तड़का लग गया है। जांजगीर-चाम्पा जिला के अकलतरा नगर पालिका की अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित सीट पर शिव सेना (शिंदे) ने 'मिस छत्तीसगढ़ 2025' पूजा टांडेकर को उतारकर सबको चौंका दिया है। पूजा टांडेकर का मुकाबला बीजेपी की शांति भारते और कांग्रेस की ज्योति जोशी से है। अकलतरा वार्ड 11 की रहने वाली 24 साल की पूजा टांडेकर खैरागढ़ संगीत महाविद्यालय से पढ़ाई भी कर रही है, और छालीवुड में दो फिल्मों में काम भी कर चुकी है, टिकटाक में लाखों फालॉवर्स के साथ मॉडलिंग को अपना कैरियर बनाने की सोच रखने वाली पूजा ने अब चुनावी मैदान में कदम रख दिया है।

मतदान से पहले ही भाजपा ने दो पार्षद सीट जीत दर्ज की

कटघोरा/दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। मतदान से पहले ही भाजपा ने दो पार्षद सीट पर जीत दर्ज की है। दरअसल 28 जनवरी नामांकन जमा करने का अंतिम दिन था। दंतेवाड़ा जिले के नगर पंचायत बारसूर के वार्ड क्रमांक एक में पार्षद के लिए सिर्फ भाजपा प्रत्याशी गीता बघेल ने ही नामांकन जमा किया है। वहीं नगर पालिका परिषद कटघोरा के वार्ड 13 में भी भाजपा प्रत्याशी शिवमति पटेल के अलावा किसी ने नामांकन नहीं भरा। इसके चलते इन दोनों जगहों पर भाजपा प्रत्याशियों ने मतदान से पहले ही जीत हासिल कर ली है। नगर पंचायत बारसूर के वार्ड क्रमांक एक में भाजपा पार्षद प्रत्याशी गीता बघेल निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। विधायक चैतराम अटामी और भाजपा जिलाध्यक्ष ने गीता को जीत की बधाई दी है। बीजेपी के पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले के नगर पंचायत बारसूर वार्ड क्रमांक 1 में भाजपा प्रत्याशी गीता बघेल ने नामांकन भरा। वहीं यह हास्यास्पद है कि कांग्रेस को बारसूर में कोई प्रत्याशी नहीं मिला।

भिलाई स्टील प्लांट में तेंदुआ दिखने से कर्मचारी दहशत में

भिलाई। भिलाई स्टील प्लांट में बीती रात एक तेंदुआ देखा गया। तेंदुआ बार एंड रॉड मिल के पास रेलवे लाइन पर जा रहा था। जिसका वीडियो शंटिंग स्टाफ भुवन सिंह ने बनाया। तेंदुए का वीडियो बनाकर संयंत्र प्रबंधन को इसके बारे में बताया। तेंदुए के घूमने की सूचना मिलते ही बीएसपी प्रबंधन ने प्लांट एरिया में तेंदुए की तलाश शुरू की, लेकिन वह नजर नहीं आया। इसके बाद बीएसपी मैनेजमेंट ने मैत्रीबाग प्रबंधन को इसकी सूचना दी। बताया जा रहा कि रोलिंग मिल पोस्ट वे-ब्रिज के पीछे लाइन नंबर 59 टॉप के पास तेंदुआ को देखा गया। लोको का प्वाइंट बदलते समय शंटिंग स्टाफ भुवन सिंह की नजर तेंदुआ पर पड़ी। जिसके बाद भुवन सिंह तुरंत इसका वीडियो बनाने लगे। इस वीडियो को उच्चाधिकारियों को भेजा गया। ठेका कंपनी के कर्मचारी के मुताबिक रात 1 बजे के आसपास की घटना है। मैत्रीबाग महाप्रबंधक डॉ एनके जैन ने बताया तेंदुआ देखे जाने की सूचना हमें मिली थी। इसके बाद हमारी टीम ने जाकर पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया है। जहां पर कोई तेंदुआ नहीं दिखा।

छत्तीसगढ़ के सिविक सेंटर में सड़क पर दिखा यमराज!

भिलाई। छत्तीसगढ़ की सड़क पर मंगलवार रात अचानक यमराज प्रकट हुए। इस यमराज ने उन सभी लोगों को पकड़ा जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। दरअसल ट्रैफिक पुलिस का यह एक नया प्रयास है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ट्रैफिक) ऋचा मिश्रा ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह के दौरान सिविक सेंटर क्षेत्र में यातायात पुलिस के आरक्षक राजेंद्र सोनी ने यमराज की वेशभूषा धारण की और बिना हेलमेट वाहन चालकों को समझाइश दी। ऋचा मिश्रा ने कहा सुरक्षित वाहन चलाने और यातायात नियमों का पालन करने के लिए समझाइश दी गई। आरक्षक राजेंद्र सोनी ने बताया कि यमराज की वेशभूषा धारण कर बिना हेलमेट वाहन चालकों को समझाइश दी। उन्हें बताया गया कि मैं एक काल्पनिक यमराज हूं यदि आप इस तरह से लापरवाही करेंगे तो सच का यमराज आपको लेने आ जाएगा। 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इस दौरान यातायात पुलिस अभियान चला रही है।

बिल्डर की कार में धमाका सीसीटीवी में कैद हुई घटना

दुर्ग। दुर्ग के भिलाई के कुरुद रोड पर एक बिल्डर की कार में धमाके की घटना हुई है। कहा जा रहा है कि नकाबपोश युवक ने कार में बम लगाया गया था, जिसके बाद धमाका हुआ। बिल्डर के ऑफिस से निकलने से ठीक पहले कार में जोरदार धमाका हुआ, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। ब्लास्ट से क्षेत्र में अफरातफरी मच गई और लोग कार से दूर भागने लगे। कार ब्लास्ट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की जा रही है। इस धमाके में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। कार ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जिसमें एक नकाबपोश युवक कार के आसपास दिख रहा है। स्मृति नगर चौकी पुलिस टीम और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक, घटना प्रकाश महोबिया के ऑफिस के पास की है जो कोहका से कुरुद जाने वाली मुख्य सड़क पर इंदु आईटी स्कूल के पास है। कार प्रकाश महोबिया के भांजे संजय बुंदेला की बताई जा रही है।

कर्नाटका बैंक के खातों में ठगी के पैसों का हेरफेर, 35 गिरफ्तार

दुर्ग। दुर्ग रेलवे स्टेशन के पास स्थित कर्नाटका बैंक शाखा में म्यूल एकांउट खाताधारकों ने ठगी के पैसों का हेरफेर करने के लिए एकाउंट खुलाकर यहां जमा किया करते थे। एसीसीयू दुर्ग एवं थाना मोहन नगर पुलिस टीम ने 15 खाताधारकों एवं 20 खाता उपलब्ध कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और अब तक 2 करोड़ 85 लाख का ट्रांजेक्शन होना पाया गया है। आरोपियों के खिलाफ धारा 317 (2), 317 (4), 318 (4), 61 (2) (क) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा दिया गया है।

मामले का खुलासा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा एवं नगर पुलिस अधीक्षक चिराग जैन ने बताया कि भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा संचालित समन्वय पोर्टल के माध्यम से थाना मोहन नगर क्षेत्र के कर्नाटका बैंक शाखा स्टेशन रोड दुर्ग म्यूल एकांउट खाताधारकों का अवलोकन पर पाया गया कि कर्नाटका बैंक शाखा ग्राउंड फ्लोर ज्वाइन हैंड्स स्टेशन रोड में कुल 111 कर्नाटका बैंक खाताधारकों के एकाउंट में देश के अलग-अलग राज्यों में अनेक लोगों से हुए सायबर फ्राड का कुल रकम करीब 86,33,247 रुपये को 111 खातों में प्राप्त किया गया है। अवैध धन लाभ अर्जित करने के लिए बैंक खातों का इस्तेमाल कर रकम प्राप्त करना पाया गया तथा उन खातो में ऑनलाइन ठगी के रकम प्राप्त हुई है। इन खातों के संबंध में दिगर राज्यों से ऑनलाइन शिकायत पंजीबद्ध होना पाया गया है।

संदिग्ध उक्त कुल 111 बैंक खातों का उपयोग ऑनलाइन ठगी के रकम प्राप्त करने में प्रयोग होने व अवैध धन लाभ अर्जित करने के लिए उपयोग में लिया जाना तथा उपरोक्त खाताधारकों द्वारा यह जानते हुए कि उक्त रकम छल से प्राप्त किया गया है तथा कई खाते जिसमें साईबर फ्राड के पैसे एक से अधिक बार जमा हुए है। उपरोक्त खाता धारको द्वारा अपराधिक षडयंत्र कर साईबर फ्राड कर अवैध धन अर्जित करना पाए जाने से उपरोक्त कुल 111 कर्नाटका बैंक म्यूल खाताधारकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। आरोपियों ने देश के अलग अलग हिस्सों से साइबर ठगी की राशि को अपने एकाउंट में लेना स्वीकार किए। बैंक खाता को किराये पर देने एवं किराये पर लेने वाले के उपर भी कार्रवाई की गई।

आरोपी खाताधारकों में प्रदीप कुमार महतो सुपेला, निखार मेश्राम दुर्ग, सुनील बारिक खुर्सीपार, सौरम कोठारी भिलाई, कमलेश साहू अंजोरा, सरिता उम्र 24 खुर्सीपार, सुधा मानिकपुरी दुर्ग, बी बड़ी रवि खुर्सीपार, अनुकुल सरावनी भिलाई, प्रेम पांडेय दुर्ग, एकता पांडेय दुर्ग, कालू हरपाल खुर्सीपार, प्रवीण कुमार भिलाई शामिल है। जबकि खाता उपलब्ध कराने वाले आरोपियों में श्वेता दुबे, टुकेवर ठाकुर, उमेंद्र पटेल शुभम रंगारी, विमल कुमार साहू, एमडी आरिफ, यशवंत टोडल, अभय प्रसाद साहू, रितेन पांडे, अमृत पाल सिंह, रंजय सिंह, अमन कुमार सिंह, अथर्व जायसवाल, आयुष सोनी, राहुल वर्मा, रॉबिन लकड़ा, रितेश जेकब, कंचन एक्का शामिल है।

जनकपुर में पहली बार नगर पंचायत चुनाव

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। जनकपुर में पहली बार नगर पंचायत चुनाव 2025 के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होने जा रहा है। दोनों पार्टियों ने अपने-अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और नामांकन दाखिल भी दाखिल कर दिए गए हैं।

भाजपा ने जनकपुर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कौशल कुमार पटेल को उम्मीदवार बनाया है। उनका नामांकन भरतपुर सोनहत क्षेत्र की विधायक रेणुका सिंह की मौजूदगी में दाखिल किया गया। रेणुका सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा ने हमेशा विकास और जनसेवा को प्राथमिकता दी है। उनका उद्देश्य नगर पंचायत में बिजली, पानी, सड़क, नाली और आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं सभी तक पहुंचाना है।

कांग्रेस ने गरीब मौर्य को अपना उम्मीदवार बनाया है। उनका नामांकन भरतपुर सोनहत के पूर्व विधायक गुलाब कमरो की मौजूदगी में दाखिल किया गया। नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए गरीब मौर्य ने कहा, मुझे सेवा और साधना का अवसर मिला है। मैं हर वार्ड में योजनाओं को लागू करूंगा और जरूरतमंदों की सहायता करूंगा। लड़कियों और लड़कों को शिक्षा के लिए 5100 रुपये का अनुदान देने की योजना है। अगर किसी को आर्थिक संकट होता है, तो उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। जनकपुर नगर पंचायत में कुल 15 वार्ड हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही हैं।

कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रवि प्रताप सिंह ने बताया कि जनकपुर नगर पंचायत कांग्रेस के पूर्व विधायक गुलाब कमरो की पहल पर बनी थी। कांग्रेस ने गरीब और पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को टिकट देकर उनकी सेवा का मौका दिया है। नामांकन के अंतिम दिन दोनों पार्टियों ने अपने-अपने उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल कर दिया। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं।

संक्षिप्त समाचार

महाकुंभ संगम में हुई भगदड़ की दुर्घटना पर मुख्यमंत्री साय ने जताया दुख

रायपुर। प्रयागराज महाकुम्भ में संगम तट पर घटित भगदड़ की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कई श्रद्धालुओं के निधन और घायल होने की खबर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अत्यंत दु:खद है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ईश्वर से दिवंगतों की आत्मा की शांति एवं घायल श्रद्धालुओं के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। सभी श्रद्धालुओं से आग्रह है कि संयम बनाए रखें और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का अनुपालन करें। मां गंगा के जिस घाट के समीप हैं, वहीं पुण्य स्नान करें।

राज्यपाल को पीएससी की कार्यवाहक अध्यक्ष शांडिल्य ने वार्षिक प्रतिवेदन सौंपा

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका से बुधवार को राजभवन में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष सुश्री रीता शांडिल्य ने मुलाकात की। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग का तेइसवां वार्षिक प्रतिवेदन डेका को सौंपा। इस अवसर पर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य डॉ. प्रवीण वर्मा, डॉ. सरिता उइके, संतकुमार नेताम, सचिव अभिजीत सिंह एवं परीक्षा नियंत्रक श्रीमती लीना कोसम उपस्थित थे।

सांसद बृजमोहन ने रेल मंत्री और डीआरएम को लिखा पत्र

रायपुर। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ प्रदेश के श्रद्धालुओं को प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए विशेष ट्रेन की सुविधा देने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रायपुर मंडल के डीआरएम को पत्र लिखा है। सांसद अग्रवाल के मुताबिक, उनके लोकसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जाना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान में उपलब्ध ट्रेनों की संख्या सीमित होने के कारण यात्रियों को लंबी प्रतीक्षा सूची और असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। सांसद बृजमोहन ने मांग की है कि रायपुर अथवा दुर्ग से प्रयागराज तक महाकुंभ अवधि के लिए विशेष ट्रेन आरंभ की जाए, ताकि श्रद्धालुओं को इस पवित्र स्नान का अवसर सहजता से प्राप्त हो सके। उन्होंने रेल मंत्री और डीआरएम से अनुरोध किया है कि श्रद्धालुओं की इस आवश्यकता को प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द उचित कदम उठाए जाए। सांसद अग्रवाल ने कहा कि महाकुंभ भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक अनूठा पर्व है, जिसमें देश के कोने-कोने से लोग श्रद्धा और आस्था के साथ शामिल होते हैं। छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को इस धार्मिक आयोजन में भाग लेने में कोई बाधा न हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।

पार्षद समीर अख्तर ने दिया इस्तीफा, निर्दलीय लड़ेंगे

रायपुर। कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद समीर अख्तर ने टिकट न मिलने पर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, निर्दलीय लडने् का ऐलान करते हुए उन्होने मंगलवार को शहीद राजीव पांडे वार्ड क्रमांक 62 से नामांकन भी दाखिल कर दिया है। बुधवार को पीसी लेकर उन्होने पार्टी के सीनियर नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पैर छूने वालों को टिकट देकर पार्टी का बंटाधार किया जा रहा है। वार्ड में जो काम उन्होने किया हैं उसके साक्षी वार्ड के नागरिक हैं, चूंकि उन्हे अपनी जीत का पूरा भरोसा है इसलिए नामांकन भरा है. जीतने के बाद भी वे पार्टी में वापस नहीं लौटेंगे। वहीं छह सीटिंग पार्षदों ने पार्टी से बगावत करते हुए नामांकन दाखिल किया है। निश्चित रूप से वे अपने वार्ड में कांग्रेस को नुकसान पहुंचायेंगे। हालांकि गुरुवार तक मान मनौव्वल का समय है, हो सकता है कुछ मान जायें। जिला संगठन से भी कुछ पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है. शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव व महापौर प्रतिनिधि भूपत महोबिया ने भी बुधवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।

आयकर अन्वेषण विंग ने दी 22 ठिकानों पर दबिश

रायपुर। आयकर अन्वेषण के 150 सदस्यीय दस्ते ने बुधवार के तड़के शहर के प्रतिष्ठित उद्योगपति के रायपुर सहित दिगर राज्यों में कार्यरत कार्यालयों, शो रुम और अन्य प्रतिष्ठानों में दबिश दी है। फिलहाल यहां पर आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही थी और इस उद्योगपति द्वारा कितने कर अपवंचन किया गया है इसका खुलासा नहीं हो पाया है। बताया जाता हैं कि इस उद्योग घराने पर काफी दिनों से आयकर विभाग की नजरें टिकी हुई थी और निरंतर कर अपवंचन की शिकायत प्राप्त होने पर यह कार्रवाई की गई है। आयकर अन्वेषण विंग की टीम ने बुधवार को छत्तीसगढ़ के साथ ही मप्र, महाराष्ट्र, उड़ीसा समेत तेलंगाना के 150 अधिकारियों के साथ रायपुर, गोंदिया, काकीनाडा समेत कुल 22 ठिकानों पर दबिश दी। उद्योगपति के रायपुर राजीव नगर स्थित निवास, जवाहर मार्केट स्थित ऑफिस, राठौर चौक स्थित गोदाम, कमीशन एजेंट्स के ऑफिस संचालित है। इसके साथ रिंगरोड स्थित जगुआर कार का शोरूम समेत भनपुरी स्थित राइस मिल में भी दबिश दी गई है और जांच चल रही है। आयकर अन्वेषण विंग ने इसके अलावा मोवा सड्डू रोड पर स्थित राइस मिल के यहां भी दबिश दी और उनके अनुपम नगर स्थित घर में जांच चल रही है और अब तक किसी तरह के सीजर की जानकारी नहीं मिली है।

निकायों में कांग्रेस के घपले-घोटालों पर आरोप पत्र लाएगी भाजपा : साव

जरूरत पड़ी तो जांच भी कराएगी, कांग्रेस में अंदरूनी आपातकाल जैसे हालात, परिवारवाद यहां भी भारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री/नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव ने कहा है कि राज्य के 10 नगर निगमों, 49 नगर पालिकाओं और 114 नगर पंचायतों में जो चुनाव हो रहा है, उसके लिए नामांकन दाखिले का काम मंगलवार को पूर्ण हो चुका है और बुधवार को नामांकन पत्रों की समीक्षा हो रही है। इस बीच अनेक स्थानों पर उन्हें (स्वयं श्री साव को) 2023 के विधानसभा, 2024 के लोकसभा चुनावों और रायपुर दक्षिण उपचुनाव के समय जैसा उत्साह था, वैसा ही उत्साह निकाय चुनावों की नामांकन रैलियों में दिखाई पड़ा है। श्री साव ने कहा कि यह बताता है कि नगरीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है और भाजपा सभी नगरीय निकायों में चुनाव जीतने वाली है। श्री साव बुधवार को एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में आहूत पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

श्री साव ने कांग्रेस में मचे अंदरूनी घमासान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस की हालत सबके सामने है। पिछले 5 दिनों में जो मंजर प्रदेशवासियों ने देखा है, उससे स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी में कैसी ऊहापोह और आपाधापी मची है, किस तरह से और कैसे प्रत्याशियों का चयन हो रहा है! श्री साव ने कहा कि यह कितनी दुर्भाग्यजनक बात है कि महापौर जैसे पद के लिए कांग्रेस के पास जमीन पर काम करने वाली कोई कांग्रेस नेत्री नहीं मिली! अपने कार्यकर्ताओं की कैसी उपेक्षा और अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया है, यह प्रत्याशियों का विश्लेषण करने पर साफ हो जाएगा। कम-से-कम महापौर के पद पर भी संगठन में, जनता के बीच काम करने वाले प्रत्याशी तक कांग्रेस लेकर नहीं आ पाई। श्री साव ने कहा कि कांग्रेस ने रायपुर नगर निगम में 15 साल राज किया। राज्य के अधिकांश नगर निगमों में कांग्रेस का बहुमत था, पर निवर्तमान महापौर, जो नगरीय निकाय के पदाधिकारी हैं, उनको कांग्रेस पार्टी ने छिपा लिया क्योंकि उन्हें पता है जनता में उनके प्रति काफी आक्रोश है। रायपुर में 15 साल में कांग्रेस ने नगर निगम में कैसी दुर्दशा की, कैसे-कैसे बड़े-बड़े घोटाले किए, रायपुर शहर की जनता के सामने है। पिछले 5 साल में प्रदेश के सारे नगरीय निकायों में कांग्रेस के लोगों ने जो दुर्दशा की है, विकास को अवरुद्ध किया है, विकास के लिए राशि नहीं दी, केवल बंदरबाँट और लूट मचाई।

कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से नामांकन रैली नहीं कर पाई, कहीं नामांकन रैली रद्द हुई, यह हालत कांग्रेस पार्टी की बन चुकी है। यह स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाने से पहले हार मान गई है। श्री साव ने कहा कि वहीं दूसरी ओर, पिछले 1 साल में नगरीय निकायों में विकास के प्रदेश की भाजपा सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में काफी काम किए हैं। हमारी सरकार ने मोदी की एक-एक गारंटी पूरी की है.हमारी सरकार जहाँ एक तरफ शहरों का सुव्यवस्थित विकास करेगी, हमारे शहर सुंदर बनें, स्वच्छ बनें, सुविधापूर्ण बनें, इसके लिए हमने योजना बनाकर काम करना प्रारंभ कर दिया है और उसे तेज गति से आगे लेकर जाएंगे।

श्री साव ने कहा कि नगर निगम में कांग्रेस ने जो शहरों की दुर्दशा की है, घपले और घोटाले किए हैं, हर एक मामले प्रदेश की जनता के सामने हैं। निकायों में कांग्रेस के घपले-घोटालों पर हम आरोप पत्र लाने वाले हैं, और समय आने पर उसकी जांच करके उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। प्रदेश की जनता के साथ अन्याय और अत्याचार किसी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्धता से काम करेगी और इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हमें जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का भरपूर आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है।

बिलासपुर भाजपा महापौर प्रत्याशी के जाति प्रमाण पत्र पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति

बिलासपुर। बिलासपुर नगर निगम चुनाव में भाजपा की महापौर प्रत्याशी पूजा विधानी के जाति प्रमाण पत्र पर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई है। निर्वाचन आयोग ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए पूजा विधानी को शाम पांच बजे तक संबंधित दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया है। पूजा विधानी ने पूरे घटनाक्रम पर कहा कि कांग्रेस ने मुझे और अशोक विधानी (पति) को हीरो-हीरोइन बना दिया है।

भाजपा प्रत्याशी पूजा विधानी के नामांकन दाखिल करने के बाद कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कांफ्रेंस कर पूजा विधानी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर सवाल उठाए थे। वहीं प्रशासन पर बीजेपी प्रत्याशी का प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए इस पर आगे की कार्रवाई करने की बात कही थी।

कांग्रेस की आपत्ति को निर्वाचन आयोग ने स्वीकार करते हुए आज शाम पांच बजे तक संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। वहीं पूजा विधानी ने जाति पर उठाई गई आपत्ति को निराधार बताते हुए कहा मैं उड़िया-तेलगु हूं। मेरा बिलासपुर में जन्म हुआ है, मेरी शिक्षा यहीं की है। मेरा जाति प्रमाण पत्र 1995 का बना हुआ है, उसमें एसडीएम का अनुमोदन भी है।

पूजा विधानी ने इसके साथ कहा कि कांग्रेस डरी हुई है, जिसकी वजह से इस तरह के हथकंडे अपना रही है। चुनाव समर में उतरे हैं तो मेहनत के साथ, जनता के मुद्दों के साथ मुकाबला करना चाहिए। कांग्रेस ने मुझे और अशोक विधानी को हीरो-हीरोइन बना दिया है।

राजधानी में बगावत के बीच कांग्रेस ने एक ही घर में दो लोगों को दी टिकट

■ **पूर्व महापौर की पत्नी अर्जुमन ढेबर को बनाया पार्षद प्रत्याशी**

रायपुर। कांग्रेस में प्रत्याशियों के घोषणा के बाद से लगातार बगावत देखने को मिल रहा है। पार्टी में विरोध इतना ज्यादा है कि राजधानी रायपुर के 70 में से सिर्फ 66 पार्षदों के नाम की ही घोषणा की गई थी। बाकी 4 नामों को रोक दिया गया था। अब खबर है कि 4 में से 1 नाम फाइनल कर लिया गया है। मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड से कांग्रेस ने पूर्व महापौर एजाज ढेबर की पत्नी अर्जुमन को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं एजाज ढेबर को पं। भगवतीचरण शुक्ल वार्ड क्रमांक 57 से टिकट मिला है। यानी एक ही घर से दो लोगों को टिकट दिया गया है।

चर्चा है कि प्रत्याशियों को बकायदा फोन कर इस बात की जानकारी दे गई है कि उन्हें नामांकन दाखिल करना है। लेकिन पार्टी की ओर से अभी कोई जानकारी नहीं आई है। नामांकन प्रकिया तो पूरी हो गई है लेकिन शेष 3 सीटों के लिए अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है।

बता दें कांग्रेस ने रायपुर नगर निगम के मौलाना अब्दुल रऊफ़ वार्ड - 45, मदर टेरेसा वार्ड-47, डॉ। राजेंद्र प्रसाद वार्ड-52, अरविंद दीक्षित वार्ड-56 में प्रत्याशियों में नेताओं के बीच खीचतान के कारण प्रत्याशियों की घोषणा की नहीं थी। आज वार्ड क्रमांक 45 से पूर्व महापौर एजाज ढेबर की पत्नी अर्जुमन ढेबर पर कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है।

समर्थकों में जश्न का माहौल

कांग्रेस पार्टी की ओर से अर्जुमन ढेबर को पार्षद प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा से उनके समर्थकों में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर अर्जुमन ढेबर को बधाई दी।

छत्तीसगढ़ में 20 जनवरी से आचार संहिता लागू हो गई है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 22 जनवरी से 28 जनवरी तक चलेगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। नगरीय निकाय चुनाव की वोटिंग 11 फरवरी को होगी और परिणाम 15 फरवरी को घोषित होंगे। इस बार नगरीय निकाय चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के माध्यम से कराए जाएंगे।

बिलासपुर नगर निगम में नहीं हुआ कोई विकास : प्रमोद

■ **भाजपा ने झूठ बोलकर प्रदेश की सत्ता की हासिल**

बिलासपुर। बिलासपुर नगर निगम में कांग्रेस ने इस बार प्रमोद नायक को अपना मेयर कैंडिडेट बनाया है। नामांकन के आखिरी दिन प्रमोद नायक ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान प्रमोद नायक ने कहा कि वो पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान शहर के हर वर्ग और हर क्षेत्र के विकास पर उनका फोकस होगा।प्रमोद नायक ने कहा कि बिलासपुर को विकसित शहर बनाने के लिए वो जी जान से मेहनत करेंगे।इस दौरान प्रमोद नायक ने कहा कि ना ही बीजेपी और ना ही उनका कोई भी प्रत्याशी उनके सामने किसी भी तरह की चुनौती खड़ी कर पाएंगे।

प्रमोद नायक ने कहा कि बिलासपुर के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी सतत प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में बिलासपुर और रायपुर की तुलना करते थे अब यह तुलना नहीं रह गई है। लेकिन बिलासपुर का जो विकास होना था वह विकास नहीं हो पा रहा है। उस विकास को हम आगे बढ़ाएंगे।बिलासपुर में सड़क बिजली पानी की जो समस्या है वह दूर करेंगे। योजनाबद्ध तरीके से काम करके जो बड़े काम नहीं हो पाए हैं उसे पूरा किया जाएगा। बिलासपुर में जो 15 ग्राम पंचायत है और नगर पंचायत एक पालिका जुड़ा है। उसमें विकास के नाम पर कुछ कमी है।पहली प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को दूर करना होगा।वहां बिजली,पानी और सड़क की व्यवस्था करने का प्रयास होगा।

प्रमोद नायक ने कहा विधानसभा चुनाव में छलावा करके भारतीय जनता पार्टी ने मत हासिल किया है। चाहे महतारी वंदन के नाम से हो, महतारी वंदन मे 20% महिलाओं को फायदा मिल रहा है। वहीं अभी 80% महिलाएं वंचित हैं। 500 रूपये में सिलेंडर देने की बात कही थी। लेकिन किसी को कोई सिलेण्डर अभी उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। इसी तरह अन्य योजना चाहे धान खरीदी का हो, खाली घोषणा पत्र में ये लोग बात किए हैं। अमली जामा किसी में नहीं पहना पा रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। स्मार्ट सिटी के नाम पर छलावा किया है उसको भी लेकर रूकावट किया है उस पर भी हम जनता के बीच जाएंगे और मतदाताओं का समर्थन हासिल करेंगे।

आपको बता दें कि 57 वर्षीय प्रमोद नायक ग्रीन गार्डन कॉलोनी में रहते हैं। एमकॉम की पढ़ाई करने वाले कांग्रेस नेता प्रमोद नायक कारोबारी हैं। कुर्मी समाज के नेता प्रमोद नायक छत्तीसगढ़ कुर्मी चेतना मंच प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। युवक कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष से लेकर प्रदेश युवक कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रह चुके हैं।इसके साथ ही जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री, प्रदेश सचिव और पूर्व शहर अध्यक्ष रहकर संगठन में काम करने का लंबा अनुभव रहा है।

ध्वनि प्रदूषण : शासन ने कोर्ट को बताया कि समिति गठित की गई है

रायपुर। ध्वनि प्रदूषण को लेकर चल रही स्वत: संज्ञान में ली गई याचिका की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविन्द्र कुमार अग्रवाल की युगल पीठ को शासन की तरफ से बताया गया छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (नियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधानों का तुलनात्मक अध्ययन तथा प्रभावकारिता का अध्ययन कर ध्वनि प्रदूषण के मामलों में अब तक की गई कार्यवाही की समीक्षा तथा उक्त अधिनियम, नियम में संशोधन के संबंध में अनुशंशा करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन के सचिव आवास एवं पर्यावरण विभाग की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है जिसमें विधि एवं विधाई कार्य विभाग के प्रतिनिधि, नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रतिनिधि, गृह विभाग के प्रतिनिधि सदस्य होंगे और सदस्य सचिव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल समिति के सदस्य होंगे।

यह समिति दो माह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तथा छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम 1985 में आवश्यक संशोधन हेतु सुझाव, अभिमत प्रस्तुत करेगी।

पूर्व की सुनवाई में हस्तक्षेप याचिकाकर्ता डॉ राकेश गुप्ता की तरफ से कोर्ट को बताया गया था कि ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के उल्लंघन पर डीजे बजाने पर कोलाहल अधिनियम के तहत पेनल्टी लगाकर छोड़ दिया जाता है।

गौरतलब है कि कोल्हान अधिनियम में पहली बार प्रकरण दर्ज होने पर 1000 की पेनल्टी या 6 साल की सजा या दोनों का प्रावधान है दूसरी बार कोल्हान अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होने पर 2000 की पेनल्टी या एक साल की सजा या दोनों का प्रावधान है अमूनन सभी सभी प्रकरणों में 1000 की पेनल्टी लगाकर छोड़ जा रहा है जबकि ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 में सजा के कड़े प्रावधान हैं। इसके जवाब में सुनवाई दिनांक 20.11.2024 को कोर्ट ने याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करने को कहा था। सुनवाई के दौरान डॉ गुप्ता की तरफ से गणेश त्यौहार और विसर्जन के दौरान ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर कार्यवाही करने की हेतु निर्देश दिए जाने के निवेदन पर समिति को निवेदन पर विचार करने हेतु कहा गया है।

निकाय चुनाव पर बैज का बड़ा बयान, आधी सीटों से ज्यादा पर कांग्रेस की जीत का दावा

रायपुर। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव की सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। उम्मीदवारों के ऐलान और नामांकन के बाद अब सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। पिछले नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने सभी 10 नगर निगमों पर कब्जा किया था। इस बार बीजेपी और कांग्रेस में कांटे का मुकाबला है। शहर की सरकार के चुनाव को लेकर मीडिया ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज से बात की। इस बातचीत में दीपक बैज ने 10 नगर निगम में आधे से ज्यादा पर जीत का दावा किया है।

दीपक बैज ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस 10 नगर निगम के आधे से ज्यादा निगम पर जीत दर्ज करेगी। दीपक बैज का यह बयान चौंकाने वाला माना जा रहा है। इससे पहले कांग्रेस का सभी नगर निगमों पर कब्जा था। दीपक बैज ने उन सीटों का खुलासा नहीं किया जिस पर वह जीतने वाले हैं, लेकिन उनका यह बयान चर्चा का विषय बन गया है।

दीपक बैज ने कांग्रेस की चुनावी तैयारी और घोषणा पत्र का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र की तैयारी कर ली है। घोषणा पत्र समिति का गठन हो गया है, बैठक हो चुकी है। राज्य के नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर और नगर निगमों के विकास पर चर्चा किया गया है। आम जनता की आवश्यक्ता के अनुसार घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। उसके बाद प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट से अनुमति मिलने के बाद इसे जारी किया जाएगा।

दीपक बैज ने बीजेपी पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया था। उसमें किए गए वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया। ऐसे में नगरीय निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र बनाकर वे क्या करेंगे।

दीपक बैज ने कहा बीजेपी को पहले विधानसभा चुनाव में किए गए घोषणा पत्र के वादों को पूरा करना था। पिछले चुनाव के वादों को अब तक पूरा नहीं किया गया है। अब नगरीय निकाय चुनाव में घोषणा पत्र बनाकर क्या करेंगे। उन्हें पिछले वादों को जनता के बीच बताना था। उन वादों में कितने वादे पूरे किए गए यह बताना था।

दीपक बैज ने बीते एक साल के बीजेपी कार्यकाल में नगरीय निकाय क्षेत्र में कोई भी काम नहीं करने का आरोप लगाया। दीपक बैज का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने नगरीय निकायों को पैसे नहीं दिए। जो पैसे हमारी सरकार ने जारी किए थे। उस राशि को वापस ले लिया गया। दीपक बैज ने कहा एक भी प्रधानमंत्री आवास शहरी क्षेत्र में नहीं बना, गरीबों का घर तोड़ा गया। इसलिए भाजपा का घोषणा पत्र पूरी तरह से ढकोसला है। हमारी पार्टी नगरीय निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है।

दीपक बैज ने कहा प्रदेश की जनता और नगर निकाय के लिए बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया है। जिसका जवाब उन्हें नगरी निकाय और पंचायत चुनाव में जनता को देना होगा। उनकी सरकार 1 साल में ही असफल हो चुकी है।उनके पास जनता के बीच जाने के लिए कोई भी मुद्दा नहीं है। इसलिए उनके पास गड़े मुर्दे उखड़ने के अलावा कोई काम नहीं बचा है। इसलिए उनके पास गड़े मुर्दे उखड़ने के अलावा कोई काम नहीं बचा है।

बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर कैंडिडेट की कमी का आरोप लगता है। इस पर दीपक बैज ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी लिस्ट देख ले की एक एक सीट पर कितने दावेदार थे। हम भाजपा को चुनौती देते हैं कि उनके यहां एक-एक वार्ड से कितने कैंडिडेट ने आवेदन किया है, उस लिस्ट को जारी करें और मैं अपनी लिस्ट दे देता हूं कि हमारे यह कितने कैंडिडेट आए थे। हमारे यहां कंपटीशन था, भाजपा में चुनाव लड़ने वालों का टोटा रहा, वहां पर सिर्फ मनोनयान हुआ है

वही भाजपा के आरोप की कांग्रेस कैंडिडेट की कमी से जूझ रही है, इस पर दीपक बैज ने कहा कि हमारी लिस्ट देख ले की एक एक सीट पर कितने दावेदार थे। हम भाजपा को चुनौती देते हैं कि उनके यहां एक-एक वार्ड से कितने कैंडिडेट ने आवेदन किया है, उसे लिस्ट को जारी करें और मैं अपनी लिस्ट दे देता हूं कि हमारे यह कितने कैंडिडेट आए थे। हमारे यहां कंपटीशन था। भाजपा में से चुनाव लड़ने वालों का टोटा रहा, वहां पर सिर्फ मनोनयन हुआ है।

बीजेपी की तरफ से कांग्रेस में नेताओं की कमी के आरोप का भी दीपक बैज ने जवाब दिया है। कांग्रेस में नेताओं की पत्नी को टिकट देना महिला कार्यकर्ताओं कमी के भाजपा के आरोप पर दीपक बैज ने कहा कि उनके पास रायपुर नगर निगम के लिए कितने महिला कैंडिडेट थे, इसकी लिस्ट जारी कीजिए ,कितनों ने टिकट मांगा। इस पर अपनी लिस्ट जारी कर देते हैं कि हमारे यहां कितने लोगों ने टिकट मांगा है। इससे स्पष्ट हो जाएगा।

कांग्रेस पर बीजेपी ने परिवारवाद का आरोप लगाया है। परिवारवाद के आरोप पर दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी को निकाय चुनाव में हार का डर सता रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को बताना चाहिए की मीनल चौबे के पति दो बार के पार्षद रहे या नहीं रहे। शिवरतन शर्मा के भतीजे को चुनाव लड़वा रहे हैं। क्या रायपुर में भाजपा अपने नेताओं की पत्नियों को नही लड़वा रहे हैं। मेरा सवाल है कि क्या यह परिवारवाद नहीं है। यह सब परिवारवाद है लेकिन बीजेपी इसे छिपा रही है। बीजेपी को सच्चाई बतानी चाहिए।

दिल्ली चुनाव में महिला वोटरों की उदासीनता

डॉ. रमेश ठाकुर

अरविंद केजरीवाल ने अपने चुनावी घोषणापत्र में एक बार फिर फ्रीबीज की झड़ी लगाई है। कितने सफल होंगे ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। पर, अब इतना जरूर है, लोग फ्री की सौगातों से ऊबने लगे है। श्रमबल को तरजीह देने वाली आधी आबादी, भी अब मुफ्त की चुनावी रेबड़ियों पर ध्यान नहीं देगी। इसी कारण जारी दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार-प्रसार में महिला वोटरों की उदासीनता बड़े पैमाने पर दिखने लगी है। पांच फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के कूदे कुल 699 उम्मीदवारों में 96 महिला कैंडिडेट भी हैं। पर, वैसा उत्साह नहीं दिखता, जितना पिछले चुनावों में दिखा था। जबकि, प्रमुख दल आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तीनों महिला वोटरों को रिझाने में मुफत के वादों की झड़ी लगाए हुए हैं। कोई 2100 रूपए देने का वादा कर रहा है तो 2500 और 3000 तक भी? फ्री बस सेवा सभी के एजेंड़ों में हैं। अब, सवाल यहां ये उठता है, इतनेलुभावने वादों के बाद भी महिला वोटरों में उत्साह क्यों नहीं है? इस डरावनी तस्वीर से न सिर्फ सफेदपोश परेशान हैं, बल्कि चुनाव आयोग भी चिंतित है। चुनावी समर में लगातार तेजी से गिरता वोटिग प्रतिशत चुनावी प्रक्रिया के अलावा लोकतंत्र के लिए भी घातक है। जबकि, बीते 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में महिलाओं का वोटिंग स्कोर पुरुषों के मुकाबले अधिक था। शायद, महिलाएं भी अब समझ चुकी हैं कि फ्री के नाम पर राजनीतिक दल उन्हें वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने लगे हैं? महिलाएं बुनियादी मुद्दों की गंभीरताओं को अच्छे से समझती हैं। राज्य तरक्की करे उसमें उनकी भागीदारी हो, को ध्यान में रखकर ज्यादातर महिलाएं मुफ्त की रेवड़ियां से तौबा करना शुरू कर दिया है। इस संबंध में एक ताजा और बेहतरीन उदाहरण सामने है। पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार में जब नीतीश कुमार ने शराब बंदी का ऐलान करके चुनाव लड़ा, तो महिलाओं ने बढ़चढ कर हिस्सा लिया और उन्हें सत्ता पर बैठा दिया। देश और सामाजिक उद्धार वाले मुद्दों के प्रति महिलाएं कितनी सजग हैं, इससे खूबशूरत उदाहरण दूसरा कोई नहीं हो सकता। केंद्रीय स्तर पर जब से आत्मनिर्भरता की अलख चहुंओर जगी है। तब, से महिलाएं भी श्रमबल को ज्यादा तवज्जो देनी लगी हैं। ये अच्छी बात है, इससे राजनीतिक दल अपनी हरकतों से बाज आएंगे। शायद यही कारण है दिल्ली में महिलाओं की चुनाव के प्रति उदासीनता है। क्योंकि, सभी दल मुद्दों-समस्याओं को छोड़कर फ्री की सेल लगाकर बैठे हैं। ऐसे दलों का पुरजोर विरोध होना ही चाहिए। विरोध से ही सरकारें टैक्सपेयर्स का पैसा बर्बाद करने से पीछे हटेंगी। महिलाओं की उदासीनता के बूते ही दिल्ली चुनाव इस बार नई तस्वीर पेश करेगा। मौजूदा सरकार की शराब पॉलिसी को लेकर महिलाएं खासी नाराज हैं। सरकार की नई शराब नीति में 'एक पर एक फ्री बोतल' पॉलिसी ने कईयों के घर बर्बाद कर दिए। जो नहीं पीता था, वो भी फ्री के चक्कर में पीने लगा। मौजूदा सरकार अगर सत्ता से बेदखल होती है, तो शराब ऑफर उसका मुख्य कारण होगा। वैसे, कम होती वोटिंग विधा की तल्ख सच्चाई से चुनाव और सियासी दल अच्छे से वाकिफ हैं। लेकिन उस हकीकत को दोनों कभी उजागर नहीं करना चाहेंगे। हकीकत ये है, चुनावों में अगर ग्रामीण, मध्यमवर्ग और महिलाएं हिस्सा न लें? तो वोटिंग प्रतिशत और धरातल में घुस जाए। वोटिंग से शिक्षित वर्ग, वर्किंग लोग लगातार दूरियां बनाने लगे हैं। मतदान के दिन वह छुट्टियां मनाते हैं, बा-मुश्किल ही घरों से उस दिन बाहर निकलते हैं। दिल्ली में इस बार जितने नए वोटर जुड़ें हैं उनमें पुरूषों के मुकाबले महिलाएं मतदाता काफी पीछे हैं। ये स्थिति तब है, जब दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने की कोशिश कर रहे तीनों प्रमुख दलों के घोषणाओं में महिलाओं से जुड़ी योजनाओं की मूसलाधार भरमारें हैं। आप, भाजपा व कांग्रेस तीनों दल आधी आबादी को अपने पाले में करने की भरसक कोशिशें में हैं।

दलित-ओबीसी मतदाता बनाएंगे दिल्ली में सरकार

रमेश सर्राफ धमोरा

दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डालने में अब कुछ दिनों का समय ही शेष रह गया है। वहां चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर है। सभी दलों के बड़े नेता अपनी-अपनी पार्टी प्रत्याशियों को जीताने के लिए जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पूरी दिल्ली में चुनावी चौसर बिछी हुई है। सट्टा बाजार में राजनीतिक दलों की हार-जीत के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी इसका पता तो 8 फरवरी को मतगणना के बाद ही चल पाएगा।

मगर दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार बड़ी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) चौथी बार सरकार बनाने के प्रयास में लगी हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) भी चाहती है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उनकी पार्टी की सरकार बने ताकि केंद्र व राज्य का झगड़ा समाप्त हो। कहने को तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। यहां की सरकार व मुख्यमंत्री के पास अन्य प्रदेशों की तरह पूरे अधिकार नहीं होते हैं। मगर दिल्ली का मुख्यमंत्री होना अपने आप में बड़ी बात है। दिल्ली से ही देश की सरकार चलती है। ऐसे में दिल्ली में जो सरकार बनती है उसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार दलित, जाट व गुर्जर मतदाताओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होने जा रही है। दिल्ली में 12 विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यहां करीबन 18 प्रतिशत दलित मतदाता है। दिल्ली की आरक्षित 12 सीटों के अलावा 18 और ऐसी विधानसभा सीटे हैं जहां दलित मतदाताओं की संख्या 15 प्रतिशत से अधिक है। ऐसे में दिल्ली की 30 विधानसभा सीटों पर दलित मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है।

दिल्ली में बवाना, सुल्तानपुर माजरा, मंगोलपुरी, करोल बाग, पटेल नगर, मादीपुर, देवली, अंबेडकर नगर, त्रिलोकपुरी, कोंडली, सीमापुरी, गोकलपुर विधानसभा सीट को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। इसके अलावा करीबन 15 से 20 अन्य ऐसी सीटें है जहां दलित मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इसलिए दिल्ली विधानसभा की 70 में से करीबन 30 सीटों पर दलित मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में सभी 12 आरक्षित सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों ने चुनाव जीता था। इसलिए आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस दलित मतदाताओं पर है। दिल्ली के अनुसूचित जाति के मतदाताओं में से 38 फीसदी जाटव और 21 फीसदी वाल्मीकि है।

पिछले लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जाति के मतदाताओं के लिए देश भर में आरक्षित 84 लोकसभा सीटों में से भाजपा मात्र 30 सीट पर ही चुनाव जीत पाई थी। इंडिया गठबंधन के भाजपा द्वारा संविधान बदलने के नारे के कारण दलित मतदाता भाजपा से छिटककर विपक्षी खेमे में चले गए थे। इसी तरह दिल्ली में भी पिछले दो विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सभी 12 सीटों पर आम आदमी पार्टी लगातार जीतती आ रही है। इसलिए अनुसूचित जाति के मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए भाजपा व कांग्रेस इस बार के चुनाव में पूरा जोर लगा रही है।

भाजपा ने 12 आरक्षित सीटों के अलावा दो सामान्य सीटों मटिया महल से दीप्ति इंदौरा व बल्लीमारन से कमल बागड़ी को उम्मीदवार बनाया है। इस तरह भाजपा ने कुल 14 सीटो पर दलित उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने भी नरेला से अनुसूचित जाति की अरुणा कुमारी को टिकट देखकर कल 13 सीटों पर दलित प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। भाजपा व कांग्रेस की रणनीति है कि दलित मतदाताओं को आम आदमी पार्टी से दूर किया जाए। आम आदमी पार्टी ने 12 आरक्षित सीटों पर ही अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों को टिकट दी है। हरियाणा व महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक बार फिर दलित मतदाताओं का रुझान भाजपा की तरफ होने के चलते वहां भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की थी। इसी से उत्साहित होकर भाजपा अनुसूचित जाति के मतदाताओं की बहुलता वाली सीटों पर विशेष चुनावी प्रबंधन कर चुनावी रणनीति बना रही है।

दिल्ली में जाट मतदाताओं की बहुलता वाली 10 सीटों महरौली, मुंडका, रिठाला, नांगलोई, मटियाला, पालम, नरेला, विकासपुरी, नजफगढ़ व बिजवासन पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। इस बार भाजपा आम आदमी पार्टी से इन सभी 10 सीटों को छीन कर अपनी वापसी का प्रयास कर रही है। भाजपा ने इस बार करीबन 14 टिकट जाट नेताओं को दी है। जिनमें पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। वही आप सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे कैलाश गहलोत भी बीजेपी टिकट पर बिजवासन से चुनाव लड़ रहे हैं। कैलाश गहलोत के भाजपा में जाने से आप के पास कोई बड़ा जाट नेता नहीं रह गया है जो जाट मतदाताओं को आप पार्टी से जोड़े रख सके। जबकि भाजपा ने पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ा कर दिल्ली के चुनाव को रोचक बना दिया है।

दिल्ली में गुर्जर मतदाताओं की भी बड़ी संख्या है। इनके प्रभाव वाली छतरपुर, मुस्तफाबाद, तुगलकाबाद, घोंडा, गोकुलपुरी, ओखला पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। वहीं बदरपुर, करावल नगर व पालम पर भाजपा का कब्जा है। दिल्ली के पूर्व सांसद व बड़े गुर्जर नेता रमेश बिधूड़ी को भाजपा ने मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के खिलाफ चुनाव मैदान में उतार कर चुनाव को रोचक बना दिया है।

दिल्ली में मदनलाल खुराना व साहिब सिंह वर्मा के बाद हमेशा बाहरी व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बनता रहा है। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, अरविंद केजरीवाल, अतिशी मार्लेना जैसे लोग दिल्ली के मूल निवासी नहीं है। इसलिए दिल्ली के लोग चाहते हैं कि अब की बार दिल्ली का ही रहने वाला नेता दिल्ली का मुख्यमंत्री बने ताकि उसे दिल्ली की असली नब्ज व समस्याओं की बखूबी जानकारी हो। जाट मतदाता चाहते हैं कि साहिब सिंह वर्मा के बाद एक बार फिर उनके बेटे प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाए ताकि दिल्ली का सर्वांगीण विकास हो सके। वही गुर्जर मतदाता रमेश बिधूड़ी को मुख्यमंत्री बनाने की का मांग कर रहे हैं।

कहने को तो कांग्रेस भी पूरी सक्रियता से चुनाव लड़ रही है। मगर इंडिया गठबंधन में उनके साथी दलों द्वारा आम आदमी पार्टी को समर्थन देने के बाद कांग्रेस का मनोबल कमजोर हुआ है। इसी के चलते कांग्रेस का चुनाव प्रचार भी ज्यादा गति नहीं पकड़ पाया है। ऐसे में मुख्य मुकाबला आप व भाजपा के मध्य माना जा रहा है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में जो संघर्ष देखने को मिल रहा है उससे लगता है कि इस बार मुकाबला नेक टू नेक होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। सभी दलो द्धारा मतदाताओं को लुभाने के लिये बड़ी-बड़ी धोषणा की जा रही है। पिछले लोकसभा चुनाव का ट्रेंड देखकर तो यही लगता है कि इस बार भाजपा, आप व कांग्रेस में से कौन सी पार्टी सरकार बनायेगी यह कोई नहीं बता सकता है। इसका फैसला तो वोट डालकर दिल्ली के मतदाता ही करेंगे। जिस पार्टी के पक्ष में दिल्ली के मतदाता मतदान करेंगे। वही पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदों में अष्टादश पुराणों के नाम

(गतांक से आगे...)

उपर्युक्त वाक्यों में जो सकाम कर्मों से स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति और पुनर्जन्म तथा संध्या-प्राणायाम से दु:खादि का नाश और मोक्ष की प्राप्ति एवं संयम, ज्ञान और तपश्चर्या से तीर्थसेवन-फल का लाभ प्रकट किया गया है, वह वस्तुत: यथार्थ है। इसलिए ऐसे वाक्यों को यथार्थ कहना चाहिये। इस प्रकार वेदादि समस्त शास्त्रों की भांति पुराणों के वाक्यों को भी रोचक, भयानक और यथार्थ नामक किसी उचित श्रेणी में वरिगणित करने के बाद उनकी अर्थसंगति बैठानी चाहिये।

भाषा-विचार- जिस प्रकार अन्वित शब्द-समुदाय को वाक्य या वचन कहते है हुसीप्रकार यथावत् अन्वित वाक्य-समुदाय को सन्दर्भ या कथानक कहा जाता है। यहाँ हमारे भाषाविचार का क्षेत्र वही कथानक या संदर्भ है।

वेदादि शास्त्रों के संदर्भों को प्राचीन ऋषियों ने भाषातत्त्व के आधार पर तीन भागों में विभक्त किया है। यथा- समाधिभाषा प्रथमा लौकिकीति तथा परा। तृतीया परकीयेति शास्त्रभाषा त्रिधा स्मृता:। (भारद्वाजसंहिता)

अर्थात्- शास्त्रों की भाषा तीन प्रकार भाषा, दूसरी- लौकिकी भाषा और तीसरी की है, पहली- समाधि- परकीया भाषा ।

समाधि-भाषा- जो बातें जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में भी पुरुष को प्रत्यक्ष न हो सकती हों और इन्द्रिय, मन: आदि भी जिन रहस्यों के अनुभव करने में समर्थ न हों ऐसे समाधिगम्य अवाङ्मनसोगोचर एवं लोकोत्तर तत्त्वों को जहां तेति नेति शब्दों द्वारा व्यक्त करने का प्रयत्न किया गया हो वह समाधि-भाषा कहलाती है। **क्रमश: ...**

महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है शहीद दिवस

अनन्या मिश्रा

देश गणतंत्र दिवस के बाद शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस के मौके पर देश शहीद जवानों को नमन करता है। हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। लेकिन कुछ लोग इस दिन को लेकर असमंजस की स्थिति में रहते हैं। तो बता दें कि हमारे देश में साल में दो बार शहीद दिवस मनाया जाता है। एक 30 जनवरी और दूसरा 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। ऐसे में आपके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि दो बार शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि 30 जनवरी को शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है।

आपको बता दें कि आज यानी की 30 जनवरी का शहीद दिवस राष्टपित महात्मा गांधी को समर्पित होती है। इस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है।

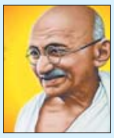

नाथूराम गोडसे ने साल 1948 को महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलाने के लिए अहिंसा का मार्ग अपनाया था। गांधीजी के निधन के बाद 30 जनवरी यानी की उनकी पुण्यतिथि को शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा।

30 जनवरी यानी की शहीद दिवस के मौके पर राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और तीनों सेना प्रमुख उनको श्रद्धांजलि देते हैं। इस मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए हथियार नीचे झुका दिए जाते हैं।

पूरी दुनिया महात्मा गांधी को प्यार से बापू कहकर बुलाती थी। वह सत्य, अहिंसा और सादगी के मार्ग पर चलने वाले असाधारण व्यक्तित्व थे। उन्होंने भारत देश को धर्मनिरपेक्ष और एक अहिंसक राष्ट्र के रूप में बनाए रखने का प्रबल समर्थन किया था। जिसके कारण महात्मा गांधी को तमाम आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था। लेकिन अंत में महात्मा गांधी के आदर्शों का पूरी दुनिया ने न सिर्फ लोहा माना, बल्कि उसको अपनाया भी है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जीवन पर्यन्त देशवासियों के लिए आदर्श नायक बने रहे। स्वतंत्रता आन्दोलन में उनके अविस्मरणीय योगदान से तो पूरी दुनिया परिचित है। अहिंसा की राह पर चलते हुए भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गांधी जी ने अपनी स्पष्टवादिता और अहिंसक विचारों से पूरी दुनिया को प्रभावित किया था। उन्हीं के द्वारा दिखलाए मार्ग पर चलते हुए लाखों-करोड़ों भारतीय देश को अंग्रेजों की दासता से मुक्त कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बने थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ईमानदारी, स्पष्टवादिता, सत्यनिष्ठा और शिष्टता के अनेक किस्से प्रचलित हैं। इन्हीं में कुछ ऐसे प्रसंग भी सामने आते हैं, जब उनकी बातें सुनकर उनके सम्पर्क में आए व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो जाता था। दरअसल लोगों के दिलोदिमाग पर उनकी बातों का जादू सा असर होता था।

नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी से काफी प्रभावित रहते थे। लेकिन 30 जनवरी 1948 की शाम नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। बता दें कि 30 जनवरी को जब गांधीजी शाम को प्रार्थना के लिए बिड़ला भवन जा रहे थे, तो उसी दौरान गोडसे ने उन पर तीन गोलियां दागी। इस हमले के बाद महात्मा गांधी ने हे राम कहकर इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।

चीनी ऐप ने छीन लिया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का चैन

नीरज कुमार दुबे

चीन आर्थिक, सैन्य और तकनीक के क्षेत्र में बादशाहत हासिल करके दुनिया का बॉस बनना चाहता है यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। चीन अपने लक्ष्य तय कर उसे हासिल करने के लिए जिस तरह चुपचाप पूरी प्रतिबद्धता के साथ जुट जाता है वह दुनिया के लिए प्रेरक भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में अमेरिकी दबदबे को चुनौती देते हुए चीनी एआई चैटबॉट डीपसीक ने जिस तरह वॉल स्ट्रीट, सिलिकॉन वैली और वाशिंगटन तथा दुनिया भर के अमीरों को सदमे में डाल दिया है उसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित है। हम आपको बता दें कि चीनी स्टार्टअप द्वारा विकसित यह ऐप इस सप्ताह अमेरिका में एप्पल स्टोर पर डाउनलोड के मामले में शीर्ष पर रहा।

कुछ विशेषज्ञों के अनुसार, डीपसीक की सफलता से पता चलता है कि चीनी एआई डेवलपर्स महंगे, उच्च-स्तरीय हार्डवेयर तक पहुंच के बिना भी अपने अमेरिकी समकक्षों की बराबरी कर सकते हैं। इस समय इंटरनेट पर मौजूद हर यूजर डीपसीक के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाह रहा है। इसलिए आइये एक नजर डालते हैं इस ऐप की खासियत और इसकी निर्माता कंपनी पर। हम आपको बता दें कि डीपसीक एक चीनी एआई स्टार्ट-अप है जिसकी स्थापना 2023 में हेज फंड हाई-फ्लायर के सह-संस्थापक लियांग वेनफेंग ने की थी। कंपनी का दावा है कि उसका एआई सॉफ्टवेयर ओपनएआई और गूगल जैसे अमेरिकी तकनीकी दिग्गजों द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर से ज्यादा प्रभावी है और इसकी लागत भी बेहद कम है।

हम आपको बता दें कि पिछले हफ्ते डीपसीक ने अपने ऐप डीपसीक-आर1 के पीछे एआई मॉडल को रेखांकित करने वाले तकनीकी बुनियादी ढांचे को प्रकाशित किया। इसमें दावा किया गया है कि आमतौर पर उन्नत एआई परियोजनाओं की तुलना में बहुत कम और कम उन्नत कंप्यूटर चिप्स का उपयोग करने से लागत में बचत होती है। इस ऐप का इंटरफ़ेस चैटजीपीटी जैसे प्रतिस्पर्धियों के समान है, जो आपको कोई भी प्रश्न या अनुरोध टाइप करने देता है, फिर

संवादी प्रतिक्रियाओं के साथ उत्तर देता है, हालांकि यह अभी तक पिक्चर्स उत्पन्न नहीं करता है। यह ऐप वर्तमान में आईओएस और एंड्रॉइड डिवाइस पर बिना किसी शुल्क के उपलब्ध है, इसलिए जो कोई भी इसका परीक्षण करना चाहता है वह कोशिश कर सकता है, हालांकि यह नए साइन-अप को सीमित कर रहा है। अन्य एआई मॉडल की तरह, डीपसीक ऐप को संचालित करने वाले पैटर्न की पहचान करने, भविष्यवाणियां करने और समस्याओं को हल करने के लिए भारी मात्रा में डेटा को संसाधित कर सकता है और उसे छान सकता है। इस एआई मॉडल को जुलाई तक के डेटा पर प्रशिक्षित किया गया है, इसलिए यह अधिक हालिया घटनाओं के बारे में नहीं जानता है, लेकिन एक खोज विकल्प अधिक नवीनतम जानकारी और सुर्खियों को स्कैन कर सकता है।

इसके अलावा, अधिकांश ऐप्स की तरह डीपसीक बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत जानकारी एकत्र और संग्रहित कर सकता है, जिसमें आपकी कोई भी बातचीत और आपके डिवाइस और इंटरनेट कनेक्शन जैसी चीज़ों के बारे में तकनीकी जानकारी शामिल है। हालांकि एक डर यह है कि उस डेटा तक चीनी सरकार पहुंच सकती है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि यह ऐप चीन के सख्त इंटरनेट नियंत्रणों के अनुरूप कुछ सूचनाओं को भी सेंसर कर रहा है, जैसे कि 1989 के तियानमेन स्क्वायर विरोध प्रदर्शन का कोई भी उल्लेख। हम आपको यह भी बता दें कि डीपसीक ने दूसरों के उपयोग और संशोधन के लिए अपने एआई मॉडल का एक संस्करण जारी किया है, बाहरी डेवलपर्स इसे एक शक्तिशाली डिवाइस पर स्थानीय रूप से चलाकर इसे अधिक सुरक्षित और कम प्रतिबंधित दोनों बना सकते हैं।

डीपसीक का दावा है कि वह अपने अमेरिकी प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम उन्नत चिप्स का उपयोग करते हुए अपनी तकनीक विकसित करने में कामयाब रहा। यह चीन की सरकार और तकनीकी उद्योग के लिए बड़ी खबर हो सकती है, क्योंकि अमेरिकी नीति निर्माता चीन के एआई विकास को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि बाइडन प्रशासन ने हाल के वर्षों में चीन के एआई के विकास को धीमा करने और एआई में अमेरिकी कंपनियों की बढ़त को बनाए रखने में मदद करने के प्रयास में सेमीकंडक्टर और ग्राफिक्स प्रसंस्करण इकाइयों या जीपीयू जैसे शक्तिशाली चिप्स के निर्यात पर व्यापक प्रतिबंध लागू किए हैं। इसके लिए अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों का हवाला दिया, हालांकि बीजिंग ने उस पर अपनी वृद्धि को रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।

डीपसीक में चैटजीपीटी और अन्य एआई मॉडल जैसे गुगल के जेमिनी, मेटा के लामा और एंथ्रोपिक के क्लाउड जैसी क्षमताएं हैं। लेकिन डीपसीक शोधकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने अपने मॉडल के मूल प्रशिक्षण और विकास को और अधिक कुशल बनाने के लिए तकनीक विकसित की है। उनके द्वारा बताए गए कुछ विचार एआई दुनिया के लिए नए नहीं हैं, लेकिन कंपनी स्पष्ट रूप से उन्हें सफल तरीके से लागू करने में सक्षम है। हम आपको यह भी बता दें कि डीपसीक ने अपने एआई मॉडल को दूसरों के लिए डाउनलोड करने और संशोधित करने के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराया है, यह रणनीति मेटा द्वारा अपने लामा एआई मॉडल के लिए भी अपनाई गई है। इसका मतलब है कि अन्य कंपनियां अपने एआई उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए डीपसीक की तकनीक का उपयोग कर सकती हैं। हम आपको बता दें कि पिछले दो वर्षों में एआई से संबंधित शेयरों की कीमतें नई ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। डीपसीक के खुलासे से कुछ निवेशकों ने सवाल उठाया है कि क्या एआई कार्यक्रम अधिक कुशल होने पर एनवीडिया जैसी चिप कंपनियां अभी भी बड़ी संख्या में चिप्स बेचने में सक्षम होंगी? हम आपको बता दें कि डीपसीक की बढ़ती लोकप्रियता के कारण टेक कंपनी के शेयरों में बिकवाली का दौर शुरू हो गया है। अग्रणी एआई चिप निर्माता एनवीडिया के शेयर की कीमत में लगभग 17 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। ऐसा ही हाल अन्य तकनीकी कंपनियों में भी देखने को मिल रहा है। विश्लेषकों ने सवाल उठाया है कि बाजार की प्रतिक्रिया ने मौजूदा चिंताओं को रेखांकित किया है कि क्या एआई के आसपास का प्रचार वास्तविक पैसा बनाने वाले उत्पादों में तब्दील होगा, और यह कितनी जल्दी होगा? अग्रणी तकनीकी कंपनियों ने नए डेटा केंद्रों पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं, इस उम्मीद में कि वे भविष्य में लाभदायक एआई सेवाओं को शक्ति प्रदान करेंगे।

हम आपको बता दें कि चीन की सरकार ने अपने अमेरिकी समकक्ष की तरह एआई को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी है और कहा है कि वह 2030 तक एआई प्रौद्योगिकी में विश्व में अग्रणी बनना चाहती है। चीन ने एआई अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में भी भारी मात्रा में पैसा निवेश किया है, ठीक उसी तरह जैसे यूएस कंपनियों ने पिछले दो वर्षों में एआई डेटा केंद्रों और विकास में अरबों डॉलर डाले हैं। हम आपको एक बार फिर याद दिला दें कि इस चिंता से कि चीन अमेरिकी सैन्य और आर्थिक शक्ति को पकड़ने के लिए एआई का उपयोग कर सकता है, बाइडन प्रशासन ने अमेरिकी चिप कंपनियों को चीन को उच्च-स्तरीय एआई हार्डवेयर निर्यात करने से रोक दिया था। लेकिन कुछ मामलों में चीनी कंपनियां अन्य देशों के माध्यम से एआई चिप्स खरीदकर इन नियंत्रणों से छुटकारा पाने में सक्षम थीं। राष्ट्रपति के रूप में अपने अंतिम हफ्तों में जो बाइडन ने चीन में एआई चिप्स की तस्करी को रोकने के लिए दुनिया के अधिकांश हिस्सों में एआई चिप निर्यात को सीमित करते हुए और भी सख्त नियंत्रण लगाए थे। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि डोनाल्ड ट्रम्प एआई निर्यात पर और भी सख्त नियंत्रण लगाने के लिए कदम उठाएंगे या नहीं। वैसे उन्होंने यह जरूर कहा है कि डीपसीक की सफलता हमारे उद्योगों के लिए एक वेक अप कॉल होनी चाहिए कि हमें जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

आज का इतिहास

1713 इंग्लैंड और नीदरलैंड ने द्वितीय एंटी फ्रांसीसी सीमा संधि पर हस्ताक्षर किये।

1737 सजीवों के शरीर में बिजली होने का पता लगाने वाले इटली के भौतिकशास्त्री और गणितज्ञ लूईची गैलवानी का बोलोनिया नगर में जन्म हुआ।

1774 कप्तान जेम्स कुक 71 डिग्री 10 दक्षिण, दक्षिण ध्रुव से 1820 किमी तक पहुंचा।

1826 मेनाई सस्पेंशन ब्रिज, जो आइल ऑफएंगलेसी और वेल्स की मुख्य भूमि को जोड़ता है, जो दुनिया के पहले आधुनिकतावादी पुलों में से एक है।

1835 रिचर्ड लॉरेंस पहले व्यक्ति बन गए जिन्होंने अमेरिका के एक राष्ट्रपति पर हत्या का प्रयास किया जब वह एंड्रयू जैक्सन को मारने में विफल रहे और भीड़ द्वारा वश में कर लिया गया।

1847 मैक्सिकन कैलिफ़ोर्निया में यर्बा बुएना शहर का नाम बदलकर सैनफ्रांसिस्को कर दिया गया था।

1858 द हॉल, यूनाइटेड किंगडम का सबसे पुराना सिम्फनीओर्केस्ट्रा, और दुनिया में चौथा सबसे पुराना, अपने पहले संगीत कार्यक्रम मैनचेस्टर का आयोजन किया।

1862 अमेरिकी नौसेना का पहला लोहा-क्लैड युद्धपोत का शुभारंभ किया गया।

1889 आस्ट्रो-हंगेरियन ताज के उत्तराधिकारी आर्चड्यूक रुडोल्फ को अपनी मालकिन बैरोनेस मैरी वेसेरा के साथ आत्महत्या करने के मामले में मिला था।

1903 लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता (तत्कालीन कलकत्ता) के मेटकाफ हॉल में 'इंपीरियल लाइब्रेरी' का उद्घाटन किया।

1911 'कैनेडियन नेवल सर्विस' का नाम बदलकर 'रॉयल कैनेडियन नेवी' किया गया।

1922 पहली बार विश्व कानून दिवस मनाया गया।

1930 सोवियत मौसम विज्ञानी पावेल मोल्चानोव ने दुनिया के पहले रेडियोसॉन्डेस में से एक को लॉन्च किया, जो विभिन्न वायुमंडलीय मापदंडों को मापने के लिए मौसम के गुब्बारे से जुड़ा एक उपकरण है।

1959 अपने युवती यात्रा के वापसी पैर पर, बेपनाह डेनिश महासागर के लाइनर हैंस हेडटॉफ्ट ने एक हिमशैल मारा और सभी हाथों से खो गया।

1964 एक रक्तहीन तख्तापलट में, जनरल गुयेन खान ने दक्षिण वियतनाम में जनरल डुआंग वान मिन्ह के सैन्य जंता को उखाड़ फेंका, तीन महीने से भी कम समय के बाद मिन्ह ने खुद एक खूनी तख्तापलट किया।

1965 ब्रिटेन के लोगों ने विंस्टन चर्चिल को अंतिम विदाई दी।

आखिर कौन लागू करवाएगा दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में आचार संहिता?

कमलेश पांडे

दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चीनी दबदबे को नियंत्रित करने के लिए एक आदर्श आचार संहिता लागू करने की मांग सही है, लेकिन वहां पर इसे लागू कौन करवाएगा, इस बात का उत्तर भारत समेत विभिन्न आसियान देशों के पास नहीं है। ये तो सिर्फ वकालत कर रहे हैं कि दक्षिण चीन सागर ऐसा होना चाहिए। जबकि चीन अपनी हठधर्मिता के चलते सैन्य कार्रवाई करने पर उतारू है। इसी दृष्टि से वह लगातार अपनी तैयारी पुख्ता करता जा रहा है। लेकिन उसे रोकने में संयुक्त राष्ट्र संघ भी यहां असहाय प्रतीत हो रहा है।

देखा जाए तो चाहे चीन विरोधी अमेरिका हो या चीन समर्थक रूस या फिर इनके-इनके समर्थक विभिन्न विकसित और विकासशील देश, सबकी नीति इस मामले में अभी तक ढुलमुल ही रही है। इसलिए भारत की भूमिका इस मामले में भी अहम और निर्णायक बताई जा रही है। क्योंकि भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के विभिन्न देशों के बहुत पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध भी हैं। वहीं, वैश्विक दुनियादारी में चीन को संतुलित रखने के लिए भी भारत और आसियान देशों को एक-दूसरे की जरूरत है। इसलिए आशियान देशों के साथ भारत की निकटता जगजाहिर है।

समझा जाता है कि भारत ही अमेरिका और रूस दोनों देशों पर दबाव डालकर आसियान देशों के दक्षिण चीन सागर सम्बन्धी दूरगामी हितों की रक्षा कर सकता है। जानकारों की मानें तो चीन की विस्तारवादी नीति से न केवल भारत बल्कि आशियान देशों के विभिन्न हित प्रभावित हो रहे हैं। उधर, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की चिंता भी किसी से छिपी हुई नहीं है। हालांकि, इन देशों में अमेरिका के बाद भारत ही एक ऐसा मुल्क है जो चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षा को नियंत्रित कर सकता है। इसी नजरिए से क्वाड देशों में भी भारत की भागीदारी प्रमुख है।

इधर भारत-चीन सम्बन्धों में भी तू डाल-डाल, मैं पात-पात वाली कहावत चरितार्थ होती है। यही वजह है कि गत 25-26 जनवरी 2025 को भारत ने चीन के खिलाफ एक और बड़ी चाल चलते हुए, दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में आचार संहिता लागू करने का आह्वान किया है। वहीं, इसके दूरगामी वैश्विक मायने को समझते हुए इंडोनेशिया जैसे प्रभावशाली देश ने भी भारत का साथ दिया है। उल्लेखनीय है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत के 76वें गणतंत्र समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। इसी दौरान हुई विभिन्न बैठकों के क्रम में उपर्युक्त आशय की सहमति बनी है।

दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती सैन्य ताकत के बीच भारत और इंडोनेशिया ने प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार इस क्षेत्र में पूर्ण और प्रभावी आचार संहिता लागू करने की वकालत की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो के बीच गत शनिवार को हुई व्यापक बातचीत में दक्षिण चीन सागर की मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में दोनों पक्षों ने भारत के हिंद महासागर क्षेत्र स्थित सूचना संलयन केंद्र (इन्फार्मेशन फ्यूजन सेंटर) में इंडोनेशिया से एक संपर्क अधिकारी तैनात करने पर सहमति व्यक्त की।

बता दें कि भारतीय नौसेना ने समान विचारधारा वाले देशों के साथ सहयोगात्मक ढांचे के तहत जहाजों की आवाजाही के साथ-साथ क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण विकास पर नजर रखने के लिए वर्ष 2018 में गुरुग्राम में इन्फार्मेशन फ्यूजन सेंटर की स्थापना की थी। चूंकि आसियान देश भी दक्षिण चीन सागर पर एक बाध्यकारी आचार संहिता पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि चीन द्वारा इस क्षेत्र पर अपने व्यापक दावों को स्थापित करने के लगातार प्रयास जारी हैं। वहीं, इस मुद्दे पर भारत की अगुवाई में चल रहे कीप एंड बैलेंस की नीति पर चीन का बौखलाना स्वाभाविक है।बीजिंग इस प्रस्तावित आचार संहिता का कड़ा विरोध करता रहा है। वह पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपनी संप्रभुता का दावा करता है, जो हाइड्रोकार्बन का एक बड़ा स्त्रोत है। जबकि, वियतनाम, फिलीपींस और ब्रुनेई सहित कई आसियान सदस्य देशों ने चीन के इस दावे पर आपत्ति जताई है।

गौरतलब है कि एक ओर दक्षिण चीन सागर में जहां चीन अपनी सैन्य ताकत में निरंतर इजाफा करने में जुटा हुआ है, जिससे आसपास के छोटे देश भयभीत हैं। वहीं अब भारत ने चीन के खिलाफ अपनी चाल चलते हुए दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में आचार संहिता लागू करने का आह्वान किया है। सुकून की बात यह है कि भारत को

इस मुद्दे पर इंडोनेशिया जैसे महत्वपूर्ण देश का भी साथ मिल गया है। जबकि दूसरी तरफ चीन इस क्षेत्र में आचार संहिता का खुलकर विरोध करता है। इसलिए दक्षिण चीन सागर से जुड़े हुए विभिन्न प्रभावित देशों के साथ-साथ भारत और अमेरिका की चिंताएं स्वाभाविक हैं।

बता दें कि अक्टूबर 2024 में भी जब पीएम मोदी ने ईस्ट एशिया सम्मेलन में हिस्सा लिया तो उन्होंने चीन पर इस बाबत निशाना साधा था। इससे एक दिन पहले आसियान-भारत सालाना सम्मेलन में भी उन्होंने चीन की तरफ इशारा करते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र और साउथ चाईना सी को लेकर जो सारी बातें कहीं, वह इस क्षेत्र में आक्रामक रवैया अपना रहे चीन को नागवार गुजर सकती है।

तब पीएम मोदी ने आसियान-भारत सालाना सम्मेलन में दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र के देशों के भौगोलिक संप्रभुता को समर्थन देकर चीन की तरफ इशारा किया था। वहीं, ईस्ट एशिया सम्मेलन में भी उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र और साउथ चाईना सी को लेकर दो टूक चिताएं जताई। मोदी ने समूचे हिंद प्रशांत क्षेत्र को कानून सम्मत बनाते हुए यहां की समुद्री गतिविधियों को संयुक्त राष्ट्र के संबंधित कानून (अनक्लोस) से तय होने की मांग की और साउथ चाईना सी के संदर्भ में एक ठोस व प्रभावी आचार संहिता बनाने की भी बात कही। बता दें कि आसियान के सभी दस सदस्य देश भी इसकी मांग कर रहे हैं।

वहीं, एक दिन पहले चीन के प्रधानमंत्री ली शियांग के साथ बैठक में आसियान नेताओं ने इन मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया था। इसके साथ ही भारतीय प्रधानमंत्री ने दुनिया के दूसरे क्षेत्रों में चल रहे तनाव के संदर्भ में कहा, विश्व के अलग-अलग क्षेत्रों में चल रहे संघर्षों का सबसे नकारात्मक प्रभाव ग्लोबल साउथ के देशों पर हो रहा है। सभी चाहते हैं कि चाहे यूरेशिया हो या पश्चिम एशिया, जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली हो।

तब पीएम मोदी ने यहां तक कहा था, मैं बुद्ध की धरती से आता हूं और मैंने बार-बार कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है। समस्याओं का समाधान रणभूमि से नहीं, बल्कि सकारात्मक रणनीति से निकल सकता है। संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का आदर करना आवश्यक है। वहीं, मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए, डायलॉग और कूटनीति को भी प्रमुखता देनी होगी। विश्वबंधु के दायित्व को निभाते हुए, भारत इस दिशा में हर संभव योगदान करता रहेगा।

तब मोदी ने आतंकवाद को भी वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बताते हुए मानवता में विश्वास रखने वाली ताकतों को एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। बता दें कि इस सालाना आसियान सम्मेलन में शामिल सभी नेताओं में सबसे ज्यादा बार (नौ बार) पीएम मोदी ने ही हिस्सा लिया है। यह आसियान के मामलों में भारत की बढ़ती भूमिका को भी बताता है।

वहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गत रविवार की शाम इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के सम्मान में डिनर आयोजित किया। इस दौरान इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने कुछ ऐसा कहा, जिसे सुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी गणमान्य लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। दरअसल, इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने भारत और इंडोनेशिया के बीच प्राचीन संबंधों की बात कहते हुए कहा कि हमारी भाषा के कई अहम शब्द संस्कृत भाषा से आते हैं।

बकौल इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, भारत और इंडोनेशिया के आपसी संबंधों का इतिहास बेहद पुराना है। दोनों देशों की सभ्यताओं में भी गहरा जुड़ाव रहा है, यहां तक कि हमारी भाषा के कई अहम शब्द संस्कृत भाषा के हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी प्राचीन भारतीय सभ्यता का प्रभाव है। यहां तक कि हमारे जीन्स यानी डीएनए में भी समानता है। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने यहां तक कहा कि %कुछ हफ्ते पहले ही मैंने अपनी जेनेटिक्स सीक्वेंसिंग और डीएनए टेस्ट कराया। मुझे बताया गया कि मेरा डीएनए भारतीय है। सभी जानते हैं कि जैसे ही मैं भारतीय संगीत सुनता हूं, तभी मैं थिरकना शुरू कर देता हूं।

वहीं, मासूमियत पूर्वक सुबियांतो ने आगे कहा कि मुझे यहां (भारत) आने पर गर्व है। मैं कोई खांटी राजनेता नहीं हूं, न ही अच्छा कूटनीतिकार हूं, मैं जो भी कहता हूं, दिल से कहता हूं। मुझे यहां आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन मैंने पीएम मोदी के नेतृत्व और उनके समर्पण से काफी कुछ सीखा है। उनका गरीबी को दूर करने और कमजोर वर्ग की मदद करने के लिए जो समर्पण है, वह हमारे लिए प्रेरणा है। इंडोनेशिया ने भारत की समृद्धि, शांति के लिए कामना की और उम्मीद जताई कि भारत और इंडोनेशिया के संबंध आगे भी मजबूत होते रहेंगे।

यही वजह है कि मोदी और सुबियांटो ने भारत-इंडोनेशिया के आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर भी चर्चा की। ताकि मजबूती पूर्वक दोनों देश अपने अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे को आगे बढ़ा सकें। इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय लेन-देन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग के लिए पिछले वर्ष हुए समझौता ज्ञापन के शीघ्र कार्यान्वयन के महत्व पर भी बल दिया। उनका मानना है कि द्विपक्षीय लेन-देन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग से व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा और दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच वित्तीय एकीकरण गहरा होगा।

वहीं, मोदी और सुबियांटो ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए भारत-इंडोनेशिया आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ाने का संकल्प दोहराया और बिना किसी दोहरे मापदंड के इस खतरे से निपटने के लिए ठोस वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया। दोनों नेताओं ने सभी देशों से संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों और उनके सहयोगियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का आह्वान किया।

इससे स्पष्ट है कि देर सबेर भारत, चीन पर दबाव बढ़ाने की अपनी रणनीति में कामयाब रहेगा। क्योंकि इस मसले पर उसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के अलावा आसियान देशों का भी साथ मिल रहा है। चूंकि रूस भारत का मित्र देश है, इसलिए उसकी तटस्थता भी भारत के लिए मायने रखेगी।

चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी की जिम्मेदारी

योगेश कुमार गोयल

भारत में लोकतंत्र की ताकत उसकी जनता है और मताधिकार वह ताकत है, जो जनता को अपनी आवाज सुनाने और देश के भविष्य को आकार देने का अवसर प्रदान करती है। 25 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला 'राष्ट्रीय मतदाता दिवस' इसी शक्ति का उत्सव है। यह दिवस न केवल भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है बल्कि इसका उद्देश्य नागरिकों को मतदान के महत्व के प्रति जागरूक करना और अधिक से अधिक लोगों को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम है 'वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम'। यह विषय इस बात पर जोर देता है कि हर नागरिक का योगदान लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और देश में घटते मतदान प्रतिशत तथा नागरिकों की चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2011 में 'राष्ट्रीय मतदाता दिवस' मनाने की शुरुआत की गई। 2025 में भारत में कुल मतदाताओं की संख्या 100 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। निर्वाचन आयोग के अनुसार, चुनावी डेटाबेस में अभी 99.1 करोड़ मतदाता हैं और यह आंकड़ा निरंतर बढ़ रहा है। देश में कुल मतदाताओं की संख्या 2004 में 67.14 करोड़, 2014 में 83.4 करोड़ और 2024 में 96.88 करोड़ थी। भारत में पहले मतदाता की पात्रता आयु 21 वर्ष थी, जिसे 61वें संशोधन विधेयक के जरिये 1988 में घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। उस संशोधन का परिणाम यह हुआ था कि वर्ष 1989 में हुए आम चुनाव में 18 से 21 वर्ष आयु वर्ग के लगभग साढ़े तीन करोड़ मतदाताओं ने पहली बार मतदान में हिस्सा लिया था। हालांकि उसके बावजूद योग्य युवा मतदाताओं द्वारा मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की रफ्तार धीमी रहने के कारण उत्साहजनक परिणाम प्राप्त नहीं हुए। इसीलिए 2011 में युवा मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत की गई थी। इस समय भारत में 18 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में 21.7 करोड़ युवा मतदाता शामिल हैं। 2024 में चुनावी लिंग अनुपात 948 था, जो 2025 में बढ़कर 954 हो गया है। यह एक सकारात्मक संकेत है कि महिला मतदाताओं की भागीदारी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लगातार बढ़ रही है। हालांकि देश में मतदान प्रतिशत अब भी चिंता का बड़ा विषय बना हुआ है। कुछ शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत अभी भी 50 प्रतिशत से कम रहता है। ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में यह आंकड़ा थोड़ा बेहतर है। मतदाता जागरूकता अभियान, डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग और ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाकर स्थिति में सुधार लाया जा सकता है।

नेतन्याहू को पीएम मोदी की बात देरी से समझ में आई?

अभिनय आकाश

यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम घर के दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रहीं हों। तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ तो मुझे तुम से कुछ नहीं कहना है।

ये पंक्तियां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता का एक अंश है। ये सवाल जो आपने सुने वो इस वक्त फिलिस्तीनी और इजरायली लोगों के सामने आकर खड़े हो गए हैं। आप सब इस खबर से तो वाकिफ अब तक हो ही गए होंगे की 19 जनवरी को गाजा में युद्ध विराम लागू हुआ और गाजा पट्टी के एक मोर्चे पर लड़ाई रुक गई। लेकिन उसके ठीक दो दिन बाद इजरायल ने फिलिस्तीन के दूसरे हिस्से में एक नया मोर्चा खोल दिया। 21 जनवरी को इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के एक रिफ्यूजी कैंप में अपना ऑपरेशन आयरन वॉल शुरू किया। एक तरफ गाजा में लोग टूटे फूटे ही सही लेकिन अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। दूसरी तरफ इजरायल में इस संघर्ष विराम को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इजरायल हमास के बीच सीजफायर समझौते के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल, हमास के साथ युद्ध विराम समझौते से नेतन्याहू सरकार के कई मंत्री नाखुश हैं और वो खुलकर इस समझौते के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। यहां तक कि कई मंत्रियों ने भी सरकार से अपना इस्तीफा दे दिया है। इस युद्ध विराम समझौते का असर नेतन्याहू के सिंहासन पर पड़ सकता है।

7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजरायल पर हमले से यह जंग शुरू हुई। इसमें 1,200 इजरायली मारे गए और 250 बंधक बना लिए गए। इजरायली ने जवाबी कार्रवाई में गाजा पर हमला किया जिसमे अब तक 46,900

फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। वहीं 20 लाख से ज्यादा बेघर हुए और 50 हजार से ज्यादा बच्चे गंभीर कुपोषण का शिकार है। हमास ने इजराइल की 4 महिला सैनिकों को रिहा कर दिया है। इसके बदले इजराइल ने भी 200 फिलिस्तीनियों को छोड़ दिया है। हालांकि कहा जा रहा है कि ये फैसला इजरायल को काफी मंहगा पड़ा है। 4 इजराइली महिला सैनिकों के बदले 200 कैदियों को छोड़ना इजराइल के लिए घाटे का सौदा साबित हुआ है। हमास और इसाइल के बीच कतर, इजिप्ट और अमेरिका ने मध्यस्थता की। कतर की राजधानी दोहा इसकी गवाह बनी। दोनों पक्ष एक ही इमारत में मौजूद थे और समझौते के ऐलान से 10 मिनट पहले तक बातचीत जारी थी। समझौते की रूपरेखा मई 2024 में बाइडेन ने पेश की। लेकिन इसी जनवरी में निर्णायक मोड़ आया।

नेतन्याहू पर इजरायली बंधकों को छुड़ाने का दवाव था। बीते 15 महीनों में इसाइल में इसके लिए 900 से ज्यादा प्रदर्शन हुए। गाजा में जंग लड़ते हुए इजरायली सेना भी थक चुकी थी। उसकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई और महंगाई भी बढ़ रही है। अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद इजरायली पर सीजफायर का दवाव और बढ़ गया था। गाजा की 90 फीसदी आबादी विस्थापित हो चुकी है। लेबनान, सीरिया, यमन और इराक तक इस संघर्ष की चपेट में आ चुके हैं और इस बात का डर लगातार बना रहा कि कहीं इजरायल और ईरान में सीधा युद्ध न शुरू हो जाए। स्वाभाविक ही शांति की यह संभावना न केवल मध्यपूर्व के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए राहत बनकर आई है।

इस सहमति के पीछे अमेरिका की भूमिका तो है ही, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इसमें निजी दिलचस्पी लेना भी खासा महत्वपूर्ण साबित हुआ है। उन्होंने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी कि उनके पद ग्रहण करने से पहले बंधक छोड़ दिए जाने चाहिए। सहमति बनने की घोषणा भी सबसे पहले ट्रंप ने ही की। इसके साथ ही इसे इस तरह से भी देख सकते हैं कि भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है जो युद्ध नहीं शांति की नीति पर चलता है। पीएम मोदी विभिन्न मंचों से साफ कर चुके हैं कि ये युद्ध का युग नहीं है। ये बात नेतन्याहू को शायद देर से ही सही पर समझ में आ गई है।

इस कथित सहमति को लेकर कई सारे सवाल बने हुए हैं। कहा जा रहा है कि अगर सहमति पर दोनों पक्ष कायम रहे रहे और इस पर अमल शुरू हुआ तो भी इस बात की गारंटी नहीं है कि इससे स्थायी शांति कायम हो ही जाएगी। पहले छह हफ्ते के युद्धविराम के दौरान जहां 33 बंधक छोड़े जाने हैं, वहीं स्थायी युद्धविराम की शर्तों पर बातचीत शुरू होनी है। आगे चलकर सारे बंधक छोड़े जाने की बात है। युद्धविराम के वाद गाजा में शासन की क्या और कैसी व्यवस्था होगी, यह भी तय होना बाकी है। बहरहाल, यह सहमति शांति के लिए एक अच्छा मौका है। उम्मीद की जानी चाहिए कि दुनिया की तमाम शांतिकामी शक्तियां इस मौके को जाया नहीं होने देंगी।

कभी कांग्रेस का गढ़ रही सुल्तानपुर माजरा से किसे चुनेगी जनता

संध्या

दिल्ली में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। अब तय हो चुका है कि कि किस सीट पर किन प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से एक सुल्तानपुर माजरा विधानसभा सीट भी है। सुल्तानपुर माजरा कभी कांग्रेस का गढ़ रही। 2015 और 2020 में इस सीट पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली। सुल्तानपुर माजरा उन सीटों में शामिल है जहां अब तक भाजपा को जीत नहीं मिली है।

कांग्रेस ने इस बार यहां से चार बार जीत चुके जय किशन को फिर से टिकट दिया है। आप ने मौजूदा विधायक मुकेश कुमार अहलावत पर फिर से विश्वास जताया है। वहीं, भाजपा के टिकट पर कर्म सिंह कर्मा मैदान में हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के इतिहास में सुल्तानपुर माजरा में कब कौन जीता? कब कितने वोट पड़े? पिछले चुनाव में कैसे नतीजे रहे थे? इस बार कैसा मुकाबला हो सकता है? आइये जानते हैं

1993 में दिल्ली को विधानसभा मिलने के बाद ही यहां पहली बार चुनाव हुए। इस चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय रहा। लड़ाई कांग्रेस, जनता दल और भाजपा के बीच हुई। इस त्रिकोणीय मुकाबले में जीत कांग्रेस को मिली। कांग्रेस के जय किशन में जनता दल के नन्द राम बागड़ी को 7412 वोटों से हराया था। भाजपा उम्मीदवार भगवान दास तीसरे स्थान पर रहे।

साल 1998 में हुए विधानसभा चुनाव में सुल्तानपुर माजरा का नतीजा एक फिर कांग्रेस के पक्ष में रहा। इस बार मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच था। कांग्रेस की सुशीला देवी ने भाजपा के कैलाश को 16933 वोटों से हराया।

2003 में हुए विधानसभा चुनाव में सुल्तानपुर माजरा के नतीजे लगातार तीसरी बार कांग्रेस के पक्ष में रहे। इस बार कांग्रेस ने पूर्व विधायक जय किशन को मैदान में उतारा था। जय किशन यहां से अपनी दूसरी और पार्टी को तीसरी जीत दिलाई। कांग्रेस के जय किशन ने भाजपा के सतीश कुमार को 18921 वोटों से हराया।

2008 में भी इस सीट पर नतीजों में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली की सत्ता में कांग्रेस लगातार तीसरी बार वापसी की। वहीं, सुल्तानपुर माजरा में पार्टी ने जीत का चौका लगाया। यहां से एक बार फिर कांग्रेस के जय किशन जीतने में सफल रहे। उन्होंने भाजपा के नन्द राम बागड़ी को हराया। बागड़ी और जय किशन के बीच 1993 में भी मुकाबला हुआ था। तब भी जय किशन ही जीतने में सफल रहे थे। कांग्रेस के जय किशन ने भाजपा के नंद लाल को 18675 वोटों से हरा दिया।

दिल्ली की राजनीति के लिए साल 2013 एक टर्निंग पाइंट साबित हुआ। इस चुनाव में मुकाबले में कांग्रेस-भाजपा के अलावा इस बार भ्रष्टाचार आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी भी थी। सुल्तानपुर माजरा विधानसभा सीट पर मुकाबला आप और कांग्रेस के बीच ही था। लेकिन कांग्रेस के जय किशन को यहां से एक बार फिर जीत मिली। कांग्रेस के जय किशन ने आप के संदीप कुमार को 1112 वोटों से हराया।

2015 में फिर से दिल्ली में विधानसभा चुनाव कराने पड़े। 2014 में मात्र 49 दिन सरकार चलाने के बाद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था। फरवरी 2014 में जब लोकपाल विधेयक पारित नहीं हो पाया तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। 2015 में फिर से चुनाव कराए गए और केजरीवाल ने 70 में से 67 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की।

इस चुनाव में सुल्तानपुर माजरा सीट पर पहली बार आप और भाजपा के बीच मुख्य मुकाबला हुआ। 64439 वोट के भारी अंतर से चुनाव जीतकर आप ने यहां अपना खाता खोला। पिछली बार इस सीट पर हारे संदीप कुमार ने बड़ी जीत दर्ज की। आप को 80269 वोट मिले, जबकि भाजपा को 15830 वोट मिले।

2020 के विधानसभा चुनाव में आप आदमी पार्टी ने फिर जबरदस्त जनादेश हासिल किया। आप को 70 में से कुल 62 सीटों पर जीत मिली। सुल्तानपुर माजरा के नतीजों की बात करें तो यहां से आप के मुकेश कुमार अहलावत को बड़ी जीत मिली। मुकेश कुमार अहलावत ने भाजपा के राम चंद्र चावरिया को 48,052 वोटों से हराया था। आप को 74573 वहीं भाजपा को 26521 वोट मिले।

अबकी बार कैसे हैं समीकरण?

2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने सुल्तानपुर माजरा सीट से मौजूदा विधायक मुकेश कुमार अहलावत को ही टिकट दिया गया है। 2020 में आप के टिकट पर वो पहली बार विधायक बने। इसके पहले वह बीएसपी से जुड़े थे और 2008 और 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन दोनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।

कांग्रेस ने चार बार इस सीट पर विधायक रहे जय किशन को मैदान में उतारा है। भाजपा ने यहां से कर्म सिंह कर्मा को टिकट दिया है। सुल्तानपुर माजरा सीट पर इस बार कुल 12 उम्मीदवार मैदान में हैं।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्वर्णिम दस वर्ष

अन्नपूर्णा देवी

जैसे-जैसे देश विकसित भारत बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना का परिवर्तनकारी प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा है। यह इस बात का प्रमाण है कि महिलाओं के विकास से महिला नेतृत्व में हुए विकास तक के सफर में हम कितना आगे आ गये हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, 'जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होता, तब तक विश्व के कल्याण की कोई संभावना नहीं है। किसी भी पंछी के लिए महज एक पंख के साथ उड़ना संभव नहीं है।' उनके इस कालजयी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी, 2015 को हरियाणा के पानीपत में 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' (बीबीबीपी) योजना की शुरुआत की थी। इस ऐतिहासिक पहल का उद्देश्य भारत में गिरते बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) पर ध्यान देना और यह सुनिश्चित करना था कि देशभर में बेटियों को वे सभी अवसर, देखभाल और सम्मान मिले, जिनकी वे हकदार हैं। वर्ष 2011 की जनगणना में बाल लिंग अनुपात 918 होने के साथ सामाजिक पूर्वाग्रहों और नैदानिक उपकरणों के दुरुपयोग की चिंताजनक तस्वीरें सामने आयीं। एक लक्ष्य के साथ 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना को न केवल इस तस्वीर को बदलने के लिए शुरू किया गया, बल्कि एक ऐसे भविष्य की नींव भी रखी गयी, जहां महिलाएं नेतृत्व की दिशा में भी आगे बढ़ सकें। बीते एक दशक में इस योजना ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली के अनुसार, जन्म के समय राष्ट्रीय लिंग अनुपात 2014-15 के 918 से बढ़कर 2023-24 में 930 हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' आंदोलन, आंकड़ों में सुधार की सीमा से कहीं आगे निकल गया है। इसने महिला सशक्तिकरण के मायने ही बदल दिये हैं। अक्तूबर 2023 में 150 महिला बाइकर्स द्वारा 10,000 किलोमीटर की यात्रा, यशस्विनी बाइक अभियान जैसी पहल, भारत की बेटियों के अदम्य साहस का प्रतीक है। वर्ष 2022 में कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव ने स्कूल न जाने वाली करीब 1,00,786 लड़कियों को फिर से स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया। कौशल विकास पर आधारित राष्ट्रीय सम्मेलन ने कार्यबल में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के महत्व पर जोर दिया, जिससे हम महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के अपने दृष्टिकोण के और करीब आ पाये। आज जब हम इस परिवर्तनकारी पहल के दस वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, साफ है कि मिशन अभी समाप्त नहीं हुआ है। हमें यदि विकसित भारत के अपने सपने को साकार करना है, तो यह तय करना जरूरी है कि बेटियां राष्ट्र निर्माण के प्रयासों के केंद्र में हों। यह हमारे लिए निर्णायक कार्रवाई करने का समय है। हमें गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम 1994 के कार्यान्वयन को मजबूत करना, शिक्षा में ड्रॉपआउट दर को संबोधित करना, कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार करना और लड़कियों के जीवन के हर चरण में उन्हें आवश्यक सहायता देनी चाहिए। वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए, भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी 41.7 प्रतिशत थी। हालांकि यह पिछले वर्षों की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि है, लेकिन फिर भी यह पुरुषों की श्रम शक्ति भागीदारी के मुकाबले कम है। भारत में बड़ी संख्या में महिलाएं अवैतनिक घरेलू देखभाल कार्य में शामिल हैं। हमारा प्रयास न केवल अधिक महिलाओं के लिए अपने घरेलू क्षेत्रों को छोड़कर घर से बाहर रोजगार करने के लिए परिवेश तैयार करना होना चाहिए।

बेहद अलग है जूलॉजी में कॅरियर

जूलॉजी में कॅरियर बनाने के लिए आपको सबसे पहले जीव विज्ञान, गणित और रसायन विज्ञान में ज्ञान प्राप्त करना होगा। 12वीं के बाद बैचलर की डिग्री हासिल करने के बाद आप इस क्षेत्र मे कदम बढ़ा सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग है, जो प्रकृति में मौजूद विभिन्न तरह के प्राणियों के बारे में गहराई से जानने की इच्छा रखते हैं। ऐसे लोग जूलॉजी में अपना करियर देख सकते हैं। जूलॉजी, जीव विज्ञान की एक शाखा है, जो मछली, सरीसृप, पक्षियों और स्तनधारियों सहित जानवरों का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह संरचना, शरीर रचना, विशेषताओं, व्यवहार, वितरण, पोषण की विधि, शरीर विज्ञान, आनुवंशिकी और पशु प्रजातियों के विकास को शामिल करता है। जूलॉजी का अध्ययन करते समय आप समुद्री जीवों, चिड़ियाघर के जानवरों और जंगली और यहां तक कि घरेलू पालतू जानवरों सहित जानवरों के जीव विज्ञान और आनुवंशिकी का अध्ययन करते हैं। ऐसे में अगर आप भी इनके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो बतौर जूलॉजिस्ट बनकर ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में

क्या होता है काम

एक जूलॉजिस्ट का मुख्य काम जानवरों के व्यवहार, विशिष्ट विशेषताओं और उनमें विकासवादी प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हैं। जूलॉजिस्ट को पशु जीवविज्ञानी या वैज्ञानिक भी कहा जाता है। यह एक बेहद विस्तृत क्षेत्र है और विभिन्न क्षेत्रों से संबंध रखने वाले जूलॉजिस्ट को अलग-अलग नामों से जाना जाता है। मसलन, पक्षियों के अध्ययन में विशेषज्ञता वाले जूलॉजिस्ट्स को ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा जाता है, वहीं मछली का अध्ययन करने वाले को आइकथोलॉजिस्ट के रूप में जाना जाता है। ठीक इसी तरह, जो जूलॉजिस्ट्स जो उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन करते हैं उन्हें हेरपेटोलॉजिस्ट नाम से जाना जाता है और स्तनधारियों से जुड़े लोगों को मैमलॉजिस्ट कहा जाता है। उनके कार्यक्षेत्र में जानवरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीड़े, मछलियों और कीड़े के पहलुओं पर रिपोर्ट तैयार करना और उन्हें विभिन्न स्थानों पर प्रबंधित करना है। जूलॉजिस्ट डीएनए पहचान सहित उच्च तकनीक के सभी प्रकार के क्षेत्र में और प्रयोगशाला में काम करते हैं, और वे जानकारी के डेटाबेक विकसित करते हैं।

योग्यता

कॅरियर एक्सपर्ट की मानें तो जूलॉजी में कॅरियर बनाने के लिए आपको सबसे पहले जीव विज्ञान, गणित और रसायन विज्ञान में ज्ञान प्राप्त करना होगा। 12वीं के बाद बैचलर की डिग्री हासिल करने के बाद आप इस क्षेत्र में कदम बढ़ा सकते हैं। हालांकि आप इस क्षेत्र में बैचलर की डिग्री के बाद मास्टर डिग्री या डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल कर सकते हैं।

व्यक्तिगत कौशल

एजुकेशन एक्सपर्ट कहते हैं कि जूलॉजी के क्षेत्र में कॅरियर देख रहे छात्रों का बेहद साहसी होना जरूरी है और उनके जीवन में डर के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्हें समर्पित, स्वतंत्र और मेहनती भी होना चाहिए। उन्हें विभिन्न लोगों के साथ काम करना आना चाहिए। चूंकि वैज्ञानिक अक्सर शोध प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, इसलिए उनके पास प्रभावी लिखित और मौखिक संचार क्षमताएं होनी चाहिए। वह अपना अधिकांश समय जानवरों के साथ बिताते हैं, इसलिए उन्हें जोखिम भरी परिस्थितियों में काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्हें काटने, खरोंचने आदि जैसे हमलों के लिए हरदम मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए और चोटों को सहने की क्षमता होनी चाहिए। जूलॉजी के क्षेत्र में आपको कई घंटों तक काम करना पड़ सकता है, जो वास्तव में आपके लिए थकाऊ हो सकता है।

संभावनाएं

बतौर जूलॉजिस्ट आप चिड़ियाघर, वाइल्डलाइफ सर्विस, बोटेनिकल गार्डन, कंसर्वेशन आर्गेनाइजेशन, नेशनल पार्क, यूनिवर्सिटी व लेबोरेटरीज आदि में काम कर सकते हैं। जहां चिड़ियाघर व म्यूजियम में वे बतौर एजुकेटर या क्यूरेटर अपना कॅरियर आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं आप स्कूल या कॉलेज में टीचर्स या रिचर्सर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। वहीं अपना शोध पूरा कर लेने के बाद आप एक स्वतंत्र शोधकर्ता के रूप में भी आगे कार्य कर सकते हैं। इसी तरह एनिमल रिहैबिलिटेटर्स या बतौर कंसर्वेशनिस्ट भी आप अपना उज्जवल भविष्य देख सकते हैं।

आमदनी

इस क्षेत्र में आपका वेतन शिक्षा, अनुभव, कार्य की प्रकृति व स्पेशलाइजेशन के आधार पर निर्भर करता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छी आमदनी हो सकती है। शुरूआती दौर में आप 10000 से 15000 रूपए महीना आसानी से कमा सकते हैं। वहीं कुछ समय के पश्चात आपकी आमदनी 25000 रूपए प्रतिमाह या इससे अधिक भी हो सकती है। अगर कुछ वर्षों के अनुभव के पश्चात आप विदेश में काम करते हैं तो आप यकीनन लाखों में कमा सकते हैं।

लेखन के क्षेत्र में बनाएं कॅरियर

ऐसे बहुत से लोग होते हैं, जिन्हें लिखना बहुत पसंद होता है। लेखन की कई विधाएं हैं, इन्हीं में से एक है क्रिएटिव राइटिंग। लेखन के क्षेत्र की यह विधा बेहद कलात्मक है। इस क्षेत्र से जुड़े लोग वास्तव में रचनात्मक लेखक हैं, जिन्हें लोग उपन्यासकार, कवि, गीतकार आदि विभिन्न नामों से जानते हैं। क्रिएटिव राइटर्स के पास लेखन में जादुई शक्ति होती है और अपने काम के माध्यम से, वे पाठकों को प्रभावित कर सकते हैं और उन्हें परेशान, घृणित, मंत्रमुग्ध या खुश कर सकते हैं। आमतौर पर लोग इस काम को आसान मानते हैं, जबकि लेखन बनाना एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें बहुत अधिक शोध और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। अगर आप भी लेखन में अपनी रूचि रखते हैं तो इस क्षेत्र में अपने कदम बढ़ा सकते हैं

क्या है क्रिएटिव राइटिंग

रचनात्मक लेखन वह लेखन है जिसमें एक लेखक का उद्देश्य गद्य और काव्य छंदों के माध्यम से अपनी भावनाओं, भावनाओं, कल्पनाशील विचारों और विचारों को व्यक्त करना है। विभिन्न तरह के लेखन जैसे उपन्यास, कविता, कहानी, नाटक, आत्मकथा, पटकथा लेखन, कॉपी लेखन आदि को रचनात्मक लेखन कहा जाता है। रचनात्मक लेखन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक दुनिया के चित्र बनाने के लिए बहुत अधिक कल्पना, अवलोकन और एक जन्मजात क्षमता की आवश्यकता होती है। विभिन्न विषयों और शैलियों पर लेख पढ़कर एक अच्छा लेखक बन सकता हैय हर तरह से जीवन का अनुभव करना और बहुत सारे मुहावरों, लहजों और स्थानीय भावों को सीखना और सुनना। वैसे तो क्रिएटिव राइटिंग कुछ लोगों को जन्मजात उपहार में मिलती है, लेकिन रचनात्मक लेखन में कोर्स करके कोई भी अपने लेखन कौशल में सुधार कर सकता है।

योग्यता

कॅरियर एक्सपर्ट कहते हैं कि रचनात्मक लेखन के क्षेत्र में किसी औपचारिक शिक्षा की विशेष आवश्यकता नहीं है। आपकी कल्पना, अवलोकन और रचनात्मकता के साथ लिखने की क्षमता ही आपके भविष्य के मार्ग प्रशस्त करती है। हालांकि अंग्रेजी साहित्य या पत्रकारिता और संचार में एक शैक्षिक पृष्ठभूमि आपके कॅरियर की राह को आसान बनाती है। वैसे भारत में कुछ संस्थान रचनात्मक लेखन में शार्ट टर्म कोर्स कराते हैं और इन पाठ्यक्रम में आवेदन करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकंडरी या 10+2 होनी चाहिए। इन पाठ्यक्रमों की न्यूनतम अवधि एक वर्ष है।

रचनात्मक लेखन के क्षेत्र में किसी औपचारिक शिक्षा की विशेष आवश्यकता नहीं है। आपकी कल्पना, अवलोकन और रचनात्मकता के साथ लिखने की क्षमता ही आपके भविष्य के मार्ग प्रशस्त करती है। हालांकि अंग्रेजी साहित्य या पत्रकारिता और संचार में एक शैक्षिक पृष्ठभूमि आपके कॅरियर की राह को आसान बनाती है।

व्यक्तिगत गुण

कॅरियर एक्सपर्ट कहते है कि एक क्रिएटिव राइटर को कल्पनाओं के आकाश में विचरने के साथ-साथ उसे कागज पर भी बेहतरीन तरीके से उतारने की कला आनी चाहिए। इसके अलावा उसके भीतर पढ़ने व नई चीजों को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, ताकि वह अपने शब्दकोश को अधिक मजबूत बना सके। चूंकि इन दिनों लेखन के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाने लगता है। इसलिए उसे कंप्यूटर का ज्ञान होना व इंटरनेट में आवश्यक सामग्री खोजने की कला आनी चाहिए। इसके अलावा उसके भीतर ऑब्जर्वेशन स्किल्स व कम्युनिकेशन स्किल्स भी मजबूत होने चाहिए। क्योंकि जब एक लेखक अपने या दूसरों के अनुभवों के पन्ने पर उतारता है तो उसका एक अलग ही प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन के जरिए उसके लेखन में भी विविधता को आसानी से देखा जा सकता है।

संभावनाएं

क्रिएटिव राइटर्स के पास अवसरों की कोई कमी नहीं है। कॅरियर एक्सपर्ट की मानें तो आप अपनी रूचि के अनुसार उपन्यास से लेकर संस्मरण, कविता, गीत, साइंस फिक्शन, रोमांस, स्क्रिप्ट, नाटक, यात्रा-वृत्तांत आदि लिख सकते हैं। इसके अलावा आप पत्र-पत्रिकाओं और समाचार पत्रों आदि के लिए रिपोर्ट, साक्षात्कार, सुविधाएँ, आलोचना और समीक्षाएं लिख सकता है। इसके अलावा, रचनात्मक लेखक वेब साइटों के लिए भी कंटेंट लिख सकते हैं या प्रिंट मीडिया के लिए लेख बना सकते हैं। आप किसी एक संस्थान से जुड़कर काम कर सकते हैं या फिर अलग-अलग संस्थानों के लिए फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं।

आमदनी

इस क्षेत्र में आमदनी आपके अनुभव व कौशल पर निर्भर करती हैं। शुरूआती दौर में एक क्रिएटिव राइटर आठ से दस हजार रूपए प्रतिमाह कमा सकता है। इसके बाद अनुभव बढ़ने के बाद आपका काम व आमदनी दोनों बढ़ती चली जाती है।

प्रमुख संस्थान

- इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली
- डॉ बाबासाहेब अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद
- नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मीडिया स्टडीज, अहमदाबाद
- कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी

एंट्री इंटरव्यू की तरह एग्जिट इंटरव्यू भी मायने रखता है

एंट्री इंटरव्यू की तरह ही किसी कंपनी का एग्जिट इंटरव्यू भी उतना ही मायने रखता है। नौकरी छोड़ने से पहले एग्जिट इंटरव्यू भले ही मात्र एचआर संबंधी औपचारिकता लगे लेकिन इसका मतलब ये नहीं हैं कि इसके लिए आप कोई तैयारी न करें। इंटरव्यू में अपने जवाबों को तैयार रखकर आप अपने लिए भविष्य में उस कंपनी के दरवाजे हमेशा खुले रख सकेंगे। आइए जानते हैं एग्जिट इंटरव्यू के लिए कुछ जरूरी टिप्सः

सकारात्मक चीजों पर फोकस

एग्जिट इंटरव्यू के संदर्भ को समझना महत्वपूर्ण है और बिना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए सच बोलना जरूरी है। करियर के इस मोड़ पर आपको सकारात्मक प्रभाव बनाने के लिए सहयोगियों और प्रबंधकों की तारीफ करना चाहिए।

वापसी की इच्छा जताएं

अगर आप अच्छे टर्म के साथ अपने कार्यकाल को ऑफिस में पूरा कर रहे हैं तो इसके लिए आपको वापसी के सारे रास्ते खुल रखने की कोशिश करना चाहिए। हमेशा जुड़े रहने की इच्छा जताएं और वहां के एल्यूमिनी नेटवर्क का हिस्सा बनने को कहें।

आभार व्यक्त करें

ऑर्गनाइजेशन में अपने कार्यकाल को सहज बनाने में मदद करने वालों के प्रति आभार जताना न भूलें। यह केवल मैनेजमेंट को आपके बारे में पॉजिटिव फील देगा।

माइक्रो पर्सपेक्टिव

अगर आपको अपने किसी साथी या वरिष्ट प्रबंधक से संबंधित कोई बात रखने की भी है तो उसे सही तरीके से रखें। कुछ अगर कहना आवश्यक भी हो तो उसे माइक्रो पर्सपेक्टिव रखें।

कंस्ट्रक्टिव फीडबैक

आपके कार्यकाल के दौरान ऐसा समय भी रहा होगा जब वहां कलह और परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। सुधारात्मक उपायों के साथ ईमानदार प्रतिक्रिया दें।

वकालत करने के लिए जानें बेसिक बातें

अदालतों में हम देखते हैं कि कानून के अनुसार ही एक पक्ष दूसरे पक्ष को चुनौती देता है और अदालतों में कानून के जानकार इसके भिन्न पक्षों की व्याख्या भी करते हैं। इन्हीं कानून के जानकारों को हम वकील कहते हैं और वकील बनने के लिए आपको लॉ की पढ़ाई करनी पड़ती है। इस पढ़ाई का का प्रथम चरण होता है एलएलबी का, यानी बैचलर आफ लॉ! वैसे कानून की पढ़ाई सिर्फ एक प्रोफेशन भर ही नहीं है, बल्कि यह उन तमाम जरूरतमंद लोगों को सिस्टम के साथ जोड़ने में एक अति महत्वपूर्ण कड़ी है, जो तमाम कारणों से अन्याय के शिकार होते हैं। जिन्हें पता तक नहीं होता है कि उन्हें कानून की जानकारी ना होने के कारण असीमित नुकसान उठाना पड़ा है। सच कहा जाए तो हमारे देश में ला प्रोफेशनल्स की जवाबदेही, किसी भी दूसरे प्रोफेशन से अधिक हो जाती है, क्योंकि यह कानून के शासन पर भरोसा पैदा करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सामान्य रूप से लॉ की पढ़ाई के लिए आपका 12वीं पास होना आवश्यक है और यह किसी भी विषय में हो सकता है। इसमें 50 परसेंट मार्क्स ही आवश्यक है और ऐसे में आपकी एज 20 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको सीएलएटी एग्जामिनेशन देना पड़ता है, जिसे कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट कहा जाता है और यह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। एग्जाम में आपसे लॉजिकल रीजनिंग, लीगल, एटीट्यूड, गणित, अंग्रेजी और जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद 5 साल के कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। सामान्यत : पांच साल के इन्टीग्रेटेड कोर्स के एंट्रेंस हेतु 200 अंकों के क्वेश्चन पेपर के लिए डेढ़ घंटे का टाइम दिया जाता है। इसमें इंग्लिश के 30 अंक, सामान्य ज्ञान के 50 अंक, लीगल एप्टीट्यूड के 20 अंक, लीगल रीजनिंग के 20 अंक होते हैं एवं 30 अंकों का एक एस्से भी लिखना होता है।

लॉ करने के बाद आपको इंटर्नशिप का कोर्स करना होता है और इस दौरान आपको काफी कुछ ट्रेनिंग मिलती है। इंटर्नशिप के बाद आपको किसी भी राज्य के स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट के लिए अप्लाई करना होता है और उसके बाद ऑल इंडिया बार कौंसिल का एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आपको प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट मिल जाता है और इसके बाद आप वकील बन जाते हैं।

हालाँकि, ग्रेजुएशन के बाद भी आप लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं और तब यह मात्र 3 साल का होता है। ग्रेजुएशन में भी आपको साधारणतया 50 परसेंट मार्क्स लाना होता है। वैसे एससी/ एसटी कटगरी स्टूडेंट्स के लिए इसमें छूट भी होती है।

लॉ की केटेगरी देखें तो मुख्यत : कॉर्पोरेट लॉ, क्रिमिनल लॉ, पेटेंट, एटर्नी, फैमिली लॉ, साइबर लॉ और बैंकिंग ला के रूप को गिनाया जा सकता है और किसी भी विषय में बाद में आप खुद को स्पेशलाइज कर सकते हैं। जैसा कि नाम के साथ ही स्पष्ट है कि पर्टिकुलर फील्ड में आप सम्बंधित क्षेत्र की विशेषज्ञता की हद तक जानकारी लेंगे।

खास बात यह भी है कि एलएलबी के बाद एलएलएम और पीएचडी जैसी विशेषज्ञता भी आप हासिल कर सकते हैं और बाद के दिनों में आप न्यायपालिका की परीक्षा देकर जज बनने की भी कोशिश कर सकते हैं।

लॉ करने के लिए देश भर के कुछ अच्छे कॉलेजों की बात करें तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इण्डिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु, नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद, नेशनल लॉ इन्स्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, भोपाल, द वेस्ट बेंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्युरीडिकल साइंस, कोलकाता, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर, हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, रायपुर, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद, डॉ राममनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, लखनऊ, राजीव गाँधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, पटियाला, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पटना, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लागल स्टडीज, कोच्चि का नाम मुख्य रूप से गिनाया जा सकता है। यूं अधिकांश यूनिवर्सिटीज में यह कोर्स उपलब्ध हैं और देश के तमाम जिलों में आपको ऐसे कॉलेज मिल जायेंगे, जहाँ से आप लॉ में एडमिशन लेकर कानून की समझ बढ़ा सकते हैं। वर्तमान में इस कोर्स के स्कोप की बात करने की जरुरत नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनल अदालती प्रैक्टिस के अलावा कॉरपोरेट वर्ल्ड में, एनजीओ में, बैंकिंग सेक्टर में, सरकार एवं उसके संस्थानों में, स्वतंत्र पत्रकारिता (फ्रीलांस जर्नलिज्म) में, सेना तक में, लॉ फर्म्स के साथ-साथन्यायिक सेवा तक में इसका विस्तार है।

सामान्य रूप से लॉ की पढ़ाई के लिए आपका 12वीं पास होना आवश्यक है और यह किसी भी विषय में हो सकता है। इसमें 50 परसेंट मार्क्स ही आवश्यक है और ऐसे में आपकी एज 20 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में कानून का शासन है। हर चीज कानून के अनुसार चलती है। कानून के अनुसार ही प्रशासन चलता है, कानून के अनुसार ही अदालतों का सिस्टम चलता है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रमुख समाचार

महाकुंभ में भगदड़ पर पीएम मोदी ने जताया दुख

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ में भगदड़ में अपने परिवार के सदस्यों को खोने वाले श्रद्धालुओं के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और इस त्रासदी को बेहद दुखद बताया। मोदी ने एक्स पर लिखा कि प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हरसंभव मदद में जुटा हुआ है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी जी से बातचीत की है और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान महाकुंभ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयोजन होता है और इसमें करीब दस करोड़ लोगों के गंगा में डुबकी लगाने की संभावना है। इस वर्ष, 144 वर्षों के बाद त्रिवेणी योग नामक एक दुर्लभ खगोलीय संयोग बन रहा है, जो इस दिन के आध्यात्मिक महत्व को और बढ़ा रहा है।

सेना को सौंपी जाए महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंधन

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार के आयोजन के संचालन में विश्वास की कमी का हवाला देते हुए, महाकुंभ मेले के प्रशासन और प्रबंधन को तत्काल भारतीय सेना को सौंपने की मांग की है। उनकी यह प्रतिक्रिया बुधवार सुबह-सुबह प्रयागराज के महाकुंभ में भगदड़ जैसी स्थिति के बाद आई है। अखिलेश ने एक्स पर लिखा कि महाकुंभ में आए संत समाज और श्रद्धालुओं में व्यवस्था के प्रति पुनर्विश्वास जगाने के लिए ये आवश्यक है कि उप्र शासन-प्रशासन के स्थान पर महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंधन तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए। अखिलेश यादव ने ने कहा कि 'विश्वस्तरीय व्यवस्था' करने के प्रचार करते हुए दावों की सच्चाई अब जब सबके सामने आ गयी है, तो जो लोग इसका दावा और मिथ्या प्रचार कर रहे थे, उन्हें इस हादसे में हत हुए लोगों की नैतिक ज़िम्मेदारी लेते हुए अपना पद त्याग देना चाहिए।

महाकुंभ को लेकर मल्लिकार्जुन खरगे की अपील

नईदिल्ली। महाकुंभ हादसे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे पीड़ितों को हर संभव मदद करें। उन्होंने कहा, महाकुंभ के दौरान तीर्थराज संगम के तट पर हुई भगदड़ से कई लोगों की जान गई है और अनेकों लोगों के घायल होने का समाचार बेहद हृदयविदारक है। श्रद्धालुओं के परिजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं और घायलों की शीघ्रातिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ की हम कामना करते हैं। उन्होंने सरकार को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आधी अधूरी व्यवस्था, वीआईपी मूवमेंट, प्रबंधन से ज्यादा स्वप्रचार पर ध्यान देना और बदइंतजामी इसके के लिए जिम्मेदार है। हजारों करोड़ खर्च करने के बावजूद ऐसी व्यवस्था होना निंदनीय है। अभी कई महत्वपूर्ण शाही स्नान बचे हैं तो केंद्र और राज्य सरकारों को अब चेत जाना चाहिए और व्यवस्था को सुधारना चाहिए ताकि आगे ऐसी अप्रिय घटनाएं न हों।

यमुना में जहर वाले बयान पर केजरीवाल की बढ़ेगी मुसीबत

नईदिल्ली। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी से उनके इस दावे का सबूत मांगा है कि हरियाणा यमुना नदी में औद्योगिक कचरा डालकर उसके पानी को जहरीला बना रहा है। केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में आपूर्ति बाधित करने के लिए हरियाणा नदी के पानी में जहर मिला रहा है। चुनाव आयोग ने केजरीवाल से बुधवार रात 8 बजे तक अपना जवाब देने को कहा था। इसने केजरीवाल को चेतावनी देने के लिए विभिन्न निर्णयों और कानूनी प्रावधानों का हवाला दिया कि यदि उनके दावे भ्रामक पाए गए तो उन्हें तीन साल तक की कैद हो सकती है। आयोग ने कहा कि इस तरह के आरोपों के गंभीर प्रभाव होते हैं क्योंकि इससे क्षेत्रीय समूहों, पड़ोसी राज्यों के निवासियों के बीच दुश्मनी पैदा हो सकती है और यह कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के लिए खतरा है।

दिल्ली के लिए कांग्रेस ने जारी किया एक और घोषणापत्र

नईदिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बुधवार को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। दिल्ली चुनाव के लिए पार्टी का घोषणापत्र जारी होने के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि गारंटी का मतलब है कि यह जनता का अधिकार है। दिल्ली के लोगों के लिए पांच गारंटी की घोषणा की गई है। अभी, दिल्ली में, व्यापार करने में आसानी नहीं बल्कि सांस लेने में आसानी चाहिए। यदि आप प्रदूषण और रासायनिक संदूषण का कोई भी पैरामीटर देखें, तो कोई भी दिल्ली की बराबरी नहीं कर सकता। दिल्ली में न तो भाजपा और न ही आप सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। दिल्ली में कांग्रेस ने सत्ता में आने पर पांच गारंटी सुनिश्चित करने का वादा किया है, जिनमें महिलाओं को 2,500 रुपये मासिक, 500 रुपये में गैस सिलेंडर और राशन किट तथा 25 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा शामिल है।

दिल्ली के चुनावी प्रचार में प्रधानमंत्री ने केजरीवाल पर किया पलटवार

यमुना जी में ही डूबेगी आप-दा वालों की लुटिया

नईदिल्ली। दिल्ली चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने घोंडा के यमुना खादर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। आज की चुनावी रैली को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री ने महाकुंभ में हुए दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मैं प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। कई लोगों को चोटें आईं। मैं लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के संपर्क में हूं। कुछ समय के लिए पवित्र स्नान की प्रक्रिया बाधित हुई लेकिन अब कुछ घंटों से यह सुचारू रूप से चल रही है।

मोदी ने कहा कि दिल्ली का ये क्षेत्र यमुना जी के तट पर बसा है। इस इलाके में तो बाबा श्याम गिरि भी विराजते हैं, मैं उनको नमन करते हुए आप सभी जनता जनार्दन को भी प्रणाम करता हूं। उन्होंने कहा कि कार्य दिवस होने के बावजूद भी आप यहां इतनी विशाल संख्या में दोपहर के समय हम सबको आशीर्वाद देने आए हैं। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी के बाद दिल्ली में बनने वाली भाजपा सरकार अपने सभी वादे समयबद्ध तरीके से पूरे करेगी। ये मोदी की गारंटी है।

अरविंद केजरीवाल और आतिशी के हरियाणा पर यमुना नदी के पानी में जहर घोलने के आरोप के बाद से सियासत तेज हो गई है। इन सबके बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर अरविंद केजरीवाल पर पलटवार किया है। मोदी ने कहा कि आप-दा वाले कह रहे हैं कि हरियाणा वाले दिल्ली के पानी में जहर मिलाते हैं। ये सिर्फ हरियाणा का नहीं बल्कि भारतीयों का अपमान है, हमारे संस्कारों का अपमान, हमारे चरित्र का अपमान है। ये वो देश है, जहां पानी पिलाना धर्म माना जाता है। इस देश के लोगों पर ऐसा झूठा आरोप कि कुछ भी बोल रहे हैं।

मोदी ने साफ तौर पर कहा कि मुझे पक्का विश्वास है कि ऐसी ओछी बाते करने वालों को दिल्ली इस बार सबक सिखाएगी। इन आप-दा वालों की लुटिया यमुना जी में ही डूबेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने राजनीतिक स्वार्थ में आप-दा वालों ने एक और घोर पाप किया है और ये पाप कभी भी माफ नहीं हो सकता है। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगा दिए हैं। हार के डर से आप-दा वाले बौखला गए हैं। क्या हरियाणा दिल्ली से अलग है? क्या हरियाणा वालों के बच्चे, परिवार और नाते-रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते। क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं।

नरेंद्र मोदी ने कहा कि हरियाणा का भेजा हुआ यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है, पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी पीता है, सभी न्यायमूर्ति और बाकी सभी सम्मानित लोग भी पीते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गलती माफ करना भारत के नागरिकों का उदार चरित्र है। लेकिन जानबूझकर, बद इरादे से पाप करने वालों को न दिल्ली कभी माफ करती है, न देश माफ करता है। मोदी ने कहा कि आप सभी को इनकी (आप-दा वालों की) एक और चाल से सावधान रहना है। आप-दा को हार का एहसास हो चुका है, इनके हर विधायक को लेकर जनता में बहुत गुस्सा है। इसलिए आप-दा और कांग्रेस ने पर्दे के पीछे एक दूसरे से गठबंधन कर लिया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आप-दा कोशिश कर रहे हैं कि उसका नहीं तो कांग्रेस का विधायक जीत जाए, ताकि बाद में मिलकर सत्ता हथियाने का काम हो जाए, ऐसे तो दिल्ली पर डबल आपदा आ जाएगी। इसलिए आपको घर-घर जाना है और सबको कहना है कि कमल निशान पर ही वोट दें। 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूटने चाहिए। आप याद रखना- आप-दा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। मोदी ने यह भी कहा कि हम योजनाएं बंद करने वालों में से नहीं हैं। हम योजनाओं को बल देने वाले लोगों में से हैं।

पीएम ने कहा कि ये दृश्य दिल्ली का मूड बता रहा है। ये दिल्ली के जनादेश के दर्शन करा रहा है। दिल्ली कह रही है- अब आप-दा के बहाने नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है- आप-दा के फर्जी वादे नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है- अब आप-दा की लूट और झूठ नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली अब एक ऐसी सरकार चाहती है। जो गरीबों के लिए घर बनाए। जो दिल्ली को आधुनिक बनाए। दिल्ली ऐसी सरकार चाहती है, जो हर घर नल से जल पहुंचाए और टैंकर माफिया से मुक्ति दिलाए। इसलिए पूरी दिल्ली आज कह रही है- 5 फरवरी आएगी, आप-दा जाएगी, भाजपा आएगी।

नरेंद्र मोदी ने कहा कि 8 तारीख के बाद जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, तो जो भी वादे आपसे किए गए हैं, वो सारे वादे समय सीमा में पूरे किए जाएंगे। ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी मतलब- गारंटी पूरा होने की गारंटी। उन्होंने कहा कि भारत के करोड़ों नागरिक विकसित भारत के संकल्प को लेकर दिनरात जुटे हुए हैं। ये बहुत जरूरी है कि विकसित भारत की राजधानी भी एक विकसित देश का मॉडल शहर बने।

जेपीसी ने स्वीकारा संशोधित विधेयक और मसौदा रिपोर्ट

सांसदों को असहमति दर्ज कराने के लिए दिया वक्त

नई दिल्ली। संसद की संयुक्त समिति ने बुधवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक की रिपोर्ट और प्रस्तावित कानून के संशोधित संस्करण को बहुमत से पारित कर दिया। इस विधेयक को 15-11 मतों से मंजूरी मिली। मंजूरी मिलने के बाद विपक्षी सदस्यों ने इस विधेयक की आलोचना की है और इसे असंवैधानिक बताया। उनका कहना है कि यह विधेयक सरकार को मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है, जिससे वक्फ बोर्ड का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। हालांकि समिति ने सांसदों को अपनी असहमति दर्ज कराने के लिए शाम 4 बजे तक का समय दिया गया है।

समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि विधेयक में किए गए कई संशोधनों ने विपक्ष की चिंताओं का समाधान किया है। उनका कहना था कि जब यह विधेयक पारित होगा, तो वक्फ बोर्ड को अपने काम को पारदर्शी और प्रभावी तरीके से करने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस विधेयक के तहत पहली बार पसमांदा मुसलमानों (जो पिछड़े वर्ग के हैं), गरीबों, महिलाओं और अनाथों को वक्फ के लाभार्थियों में शामिल किया गया है।

साथ ही मामले में वरिष्ठ भाजपा नेता ने बताया कि वक्फ (संशोधन) विधेयक की रिपोर्ट गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी जाएगी। साथ ही जब पत्रकारों ने मामले में पूछा कि क्या विधेयक 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में पारित होगा, तो उन्होंने कहा कि अब यह फैसला संसद और संबंधित अधिकारियों को करना है। समिति ने 8 अगस्त 2024 को अपने गठन के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में 38 बैठकें कीं और हितधारकों से परामर्श करते हुए निष्कर्ष पर पहुंची।

विपक्षी सांसदों ने इस प्रक्रिया को अलोकतांत्रिक बताया है। साथ ही आरोप लगाया कि उन्हें अंतिम रिपोर्ट का अध्ययन करने और अपनी असहमति व्यक्त करने के लिए बहुत कम समय दिया गया। शिवसेना (यूबीटी) सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि सभी विपक्षी सदस्य अपनी असहमति दर्ज कराएंगे।

साथ ही विपक्षी दलों, जैसे कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, आप और एआईएमआईएम के सांसदों ने विधेयक की तीखी आलोचना की। कुछ विपक्षी सांसदों ने अपनी असहमति दर्ज कराई है, जबकि अन्य ऐसा करने के लिए शाम 4 बजे तक समय ले रहे थे। वे यह आरोप लगा रहे हैं कि 655 पन्नों की रिपोर्ट उन्हें बहुत कम समय में दी गई और इसे पढ़ने का समय नहीं मिला।

विधेयक में एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि वक्फ द्वारा उपयोगकर्ता का खंड हटाया गया है, और यह साफ किया गया है कि वक्फ संपत्ति से संबंधित मामले अब पूर्वव्यापी तरीके से नहीं खोले जाएंगे, जब तक कि वे विवादित न हों या सरकारी संपत्ति न हों। इसके अलावा, वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने का समर्थन किया गया है, ताकि वे वक्फ मामलों में रुचि रखने वाले या विवादों में पक्षकार बन सकें।

बता दें कि विधेयक के तहत, विवादों से जुड़े मामलों में जिला कलेक्टर की जांच शक्ति को खत्म कर दिया गया है और राज्य सरकार को अब इन मामलों की जांच करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी नामित करने का अधिकार मिल गया है।

विधेयक में वक्फ बोर्डों के संचालन में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जैसे कि अब बोर्ड में गैर-मुस्लिम और कम से कम दो महिला सदस्यों को नामित किया जाएगा। इसके अलावा, केंद्रीय वक्फ परिषद में एक केंद्रीय मंत्री, तीन सांसद, दो पूर्व न्यायाधीश, चार राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी होंगे, जिनमें से कोई भी इस्लामी धर्म से संबंधित नहीं होगा।

संसदीय समिति ने वक्फ विधेयक की समीक्षा के बाद 655 पन्नों की रिपोर्ट जारी की, जिसमें सभी बदलावों को शामिल किया गया है जो विधेयक के सदस्यों द्वारा सुझाए गए थे। हालांकि, विपक्ष ने आरोप लगाया है कि उनके द्वारा किए गए संशोधनों को इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है।

इसके बाद समिति ने यह स्पष्ट किया है कि संशोधित कानून लागू होने के बाद मौजूदा वक्फ संपत्तियों की जांच नहीं की जाएगी, अगर वे संपत्तियां विवादित नहीं हैं या सरकार की संपत्ति नहीं हैं। बता दें कि समिति ने 14 संशोधनों को मंजूरी दी है, जिनमें अधिकतर संशोधन भाजपा या उसके सहयोगी सांसदों द्वारा सुझाए गए हैं।

गौरतलब है कि वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया था और इसे 8 अगस्त 2024 को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा गया था। इस विधेयक का उद्देश्य 1995 में बने वक्फ अधिनियम में संशोधन करना है ताकि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विनियमन से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सके।

खेल

प्रमुख समाचार

भुवनेश्वर चरण के लिये महिला हॉकी टीम की घोषणा

नईदिल्ली। अनुभवी स्ट्राइकर वंदना कटारिया को एफआईएच प्रो लीग के भुवनेश्वर चरण के लिये भारत की 24 सदस्यीय महिला हॉकी टीम में चुना गया है जबकि युवा फॉरवर्ड सोनम को भी स्टैंडबाय के रूप में जगह मिली है। भारत को 15 फरवरी से होने वाले टूर्नामेंट में इंग्लैंड, नीदरलैंड, स्पेन और जर्मनी से दो दो बार खेलना है। भारतीय टीम की कमान एक बार फिर सलीमा टेटे के हाथ में होगी जबकि फॉरवर्ड नवनीत कौर उपकप्तान होंगी।

महिला एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफी टीम से बाहर कटारिया के अलावा अनुभवी डिफेंडर निक्की प्रधान, ज्योति छत्री , मिडफील्डर बलजीत कौर और फॉरवर्ड मुमताज खान तथा रूतुजा डडास भी टीम में हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच हरेंद्र सिंह ने कहा टीम में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण है जो शीर्ष स्तर के टूर्नामेंट के लिये जरूरी भी है। गोलकीपर बांवरी सोलंकी, डिफेंडर अक्षता ढेकाले और ज्योति सिंह, फॉरवर्ड साक्षी राणा, अन्नु और सोनम को स्टैंडबाय के रूप में शामिल किया गया है। उन्नीस वर्ष की सोनम ने महिला हॉकी इंडिया लीग में शानदार प्रदर्शन किया और सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर रही। हरेंद्र ने कहा ,'' हमें टीम की तैयारियों पर यकीन है और हमारा मानना है कि यह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों के खिलाफ शानदार प्रदर्शन कर सकती है।''

भारतीय टीम- गोलकीपर: सविता और बिछू देवी खारीबाम, डिफेंडर: सुशीला चानू, निक्की प्रधान, उदिता, ज्योति, इशिका चौधरी और ज्योति छत्री, मिडफील्डर: वैष्णवी विट्ठल फाल्के, नेहा, मनीषा चौहान, सलीमा टेटे, सुनेलिटा टोप्पो, लालरेम्सियामी, बलजीत कौर, शर्मिला देवी। फॉरवर्ड: नवनीत कौर, मुमताज खान, प्रीति दुबे, रूतुजा पिसाल, ब्यूटी डुंगडुंग, संगीता कुमारी, दीपिका और वंदना कटारिया।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 632 अंक चढ़ा निफ्टी 23,150 के पार

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजारों में 29 जनवरी को लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली, जिसमें निफ्टी 23,150 के ऊपर बंद हुआ। बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 631.55 अंक या 0.83% बढ़कर 76,532.96 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 205.85 अंक या 0.90% की बढ़त के साथ 23,163.10 पर बंद हुआ। दिन का अंत होते-होते मार्केट में तेजी दिखने को मिली, क्योंकि निफ्टी50 के 50 में से 42 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। श्रीराम फाइनेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा मोटर्स, एसबीआई लाइफ और ट्रेंट ने सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज की और ये शेयर 3.98% तक चढ़े। वहीं, भारती एयरटेल, आईटीसी होटल्स, मारुति सुजुकी इंडिया, ब्रिटानिया और एशियन पेंट्स उन 8 शेयरों में शामिल रहे, जो नुकसान के साथ बंद हुए, जिनमें 3.53% तक की गिरावट देखी गई। 30 शेयरों वाले ब्लू-चिप इंडेक्स में जोमेटो करीब 7% उछला।

बैंकों, एनबीएफसी के दंडात्मक शुल्क पर कोई जीएसटी नहीं

नयी दिल्ली । सीबीआईसी ने कहा है कि बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के दंडात्मक शुल्क लगाने पर माल और सेवा कर (जीएसटी) लागू नहीं होगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक परिपत्र के जरिये यह भी साफ किया कि ऑनलाइन मंच पर भुगतान एग्रिगेटर्स की मदद से 2,000 रुपये तक के लेनदेन पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। बैंकों और एनबीएफसी के दंडात्मक शुल्क लगाने पर जीएसटी लागू होने के मुद्दे को स्पष्ट करते हुए सीबीआईसी ने कहा कि आरबीआई जिन संस्थाओं को विनियमित करता है। उनके दंडात्मक शुल्क अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर लगाए जाते हैं, और इसलिए उन पर जीएसटी लागू नहीं होगा।

मोतिलाल ओसवाल का नया सेक्टोरल फंड लॉन्च

नईदिल्ली। मोतिलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने अपना नया फंड ऑफर (एनएफओ) 'मोतिलाल ओसवाल इनोवेशन अपॉर्च्युनिटीज फंड' लॉन्च किया है। यह एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम है, जो इनोवेशन थीम को फॉलो करेगी। इस फंड का नया फंड ऑफर 29 जनवरी 2025 से 12 फरवरी 2025 तक खुला रहेगा। इस फंड का मकसद लॉन्ग-टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन (लंबे समय में पूंजी वृद्धि) हासिल करना है, हालांकि निवेश पर गारंटी नहीं दी जा सकती कि यह लक्ष्य पूरा होगा। यह स्कीम इक्विटी स्कीम- सेक्टोरल/थीमैटिक कैटेगरी में आती है, यानी इसका निवेश एक खास सेक्टर या थीम से जुड़ा होगा। अगर आप इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं, तो यह फंड आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हालांकि, निवेशकों को यह ध्यान रखना होगा कि इस फंड के रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है।

भारत का पहला एमएससीआई ट्रैकिंग ईटीएफ लॉन्च

नईदिल्ली। कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने बुधवार, 29 जनवरी को कोटक एमएससीआई इंडिया ईटीएफ लॉन्च किया है, जो भारत का पहला एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) है। यह एक ओपन-एंडेड ईटीएफ है, जो एमएससीआई इंडिया इंडेक्स को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। कोटक का यह न्यू फंड ऑफर (एनएफओ) खासतौर पर उन निवेशकों के लिए पेश किया गया है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नजरिया रखते हैं और भारत की संभावित विकास यात्रा में भाग लेने का अवसर तलाश रहे हैं। इस स्कीम का एनएफओ बुधवार 29 जनवरी से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। निवेशक 12 फरवरी तक कोटक के इस एनएफओ पर दांव लगा सकते हैं। एनएफओ के दौरान निवेश करने के लिए निवेशकों को प्रति यूनिट 10 रुपये का भुगतान करना आवश्यक है।

आर्थिक समृद्धि में महाकुंभ का योगदान

प्रो. अश्विनी महाजन

हर 12 वर्ष में एक बार लगने वाला महाकुंभ मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुरू हो चुका है। इस वर्ष तेरह जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ मेला आध्यात्मिक ही नहीं, अपनी विशालता और श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए दुनिया के लिए एक अद्भुत आयोजन भी है। यह पवित्र समागम सदियों पुरानी परंपराओं और सांस्कृतिक भव्यता को भी दर्शाता है। इस महोत्सव की उत्पत्ति हिंदू पौराणिक कथाओं में निहित है। इसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है, जिनके अनुसार समुद्र मंथन के पश्चात कुंभ मेले का आयोजन शुरू हुआ। मान्यता है कि समुद्र मंथन से जो अमृत का पात्र निकला था, उसे लेकर जब देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ, तो अमृत की चार बूंदें भारत के चार स्थानों पर गिरीं- प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तभी से ये स्थल कुंभ मेले के पवित्र स्थल बन गये।

यह दुनिया का सबसे बड़ा समागम है, जिसमें लगभग 40 करोड़ लोग हिस्सा लेने वाले हैं। महाकुंभ के पहले ही दिन,13 जनवरी, 2025 को, पौष पूर्णिमा स्नान के अवसर पर 1.5 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगायी, तो 14 जनवरी, 2025 को मकर संक्रांति के अवसर पर 3.5 करोड़ लोगों ने। माना जा रहा है कि मौनी अमावस्या स्नान, जो 29 जनवरी को होगा, उसमें कम से कम 10 करोड़ लोग भाग लेंगे। तीन फरवरी को बसंत पंचमी स्नान, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा स्नान और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि स्नान को मिलाकर कुल छह अमृत स्नान हैं।

दुनिया के लिए यह किसी अचंभे से कम नहीं है कि एक ही स्थान पर 40 करोड़ श्रद्धालु आयेंगे। इसके लिए प्रशासन ने

प्रयागराज में मेला स्थान को 3,200 हेक्टेयर से बढ़ाकर 4,000 हेक्टेयर कर दिया है। घाटों की लंबाई 12 किलोमीटर कर दी गयी है जो 2009 में मात्र आठ किलोमीटर ही थी। विदित हो कि कुंभ मेला एक स्थान पर नहीं, बल्कि ज्योतिषीय गणना के आधार पर चार अलग-अलग स्थानों पर लगता है। कुंभ मेले में 12 वर्ष के अंतराल का कारण यह है कि बृहस्पति को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 12 वर्ष लगते हैं।

कुंभ मेला वेबसाइट के अनुसार, जब बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं और सूर्य तथा चंद्रमा क्रमशः मेष व धनु राशि में होते हैं तो हरिद्वार में कुंभ आयोजित किया जाता है। जब बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं और सूर्य व चंद्रमा मकर राशि में होते हैं, तो कुंभ प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं, सूर्य और चंद्रमा कर्क राशि में होते हैं, तो कुंभ नासिक तथा त्रयंबकेश्वर में आयोजित किया जाता है।

यह आयोजन आर्थिक गतिविधियों का समागम भी है। जानकारों का मानना है कि 45 दिनों तक चलने वाला महाकुंभ मेला देश की जीडीपी में एक प्रतिशत तक की वृद्धि कर सकता है। प्रदेश की जीडीपी में तो उससे कहीं ज्यादा वृद्धि हो सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की गणना के अनुसार, महाकुंभ में अपेक्षित 40 करोड़ लोग पांच हजार रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च करें, तो इससे दो लाख करोड़ रुपये का आर्थिक प्रभाव होगा। लेकिन कुछ अन्य लोगों का मानना है कि प्रति व्यक्ति खर्च 10 हजार रुपये तक हो सकता है, जिसका अर्थ है चार लाख करोड़ रुपये का आर्थिक प्रभाव। यह गणना बिना आधार के नहीं है।

योगी आदित्यनाथ के अनुसार, 2019 के कुंभ ने 1.2 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त जीडीपी का सृजन किया था। इस मेले में 24 करोड़ लोगों ने भाग लिया था, जो 2013 के मेला से दोगुना था। यानी इस बार 40 करोड़ लोगों की अपेक्षित भागीदारी के चलते चार लाख करोड़ रुपये का आर्थिक प्रभाव अस्वाभाविक नहीं है। सरकार द्वारा इस मेले में 7,500 करोड़ रुपये खर्च किया जाना है, जिसमें राज्य सरकार का हिस्सा 5,400 करोड़ और केंद्र सरकार का हिस्सा 2,100 करोड़ रुपये का है। योगी आदित्यनाथ का यह भी कहना है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा अस्थायी शहर है। कुंभ मेला एक विशाल हिंदू तीर्थयात्रा और त्योहार है।

रायपुर को एक नयी पहचान दिलाकर स्वच्छ और विकसित राजधानी बनाएंगे: मीनल चौबे

रायपुर । राजधानी रायपुर से भारतीय जनता पार्टी की महापौर प्रत्याशी श्रीमती मीनल चौबे ने आज सुबह प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत, रायपुर दक्षिण के विधायक सुनील सोनी रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लोकतंत्र की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इनमें चुनाव होने जा रहे हैं। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि रायपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की महापौर प्रत्याशी श्रीमती मीनल चौबे और 70 वार्डों के पार्षद प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं सभी को शुभकामनाएं प्रदान करता हूं।महापौर प्रत्याशी श्रीमती मीनल चौबे को नगर निगम में पार्षद सहित नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करने का लंबा अनुभव है इसका लाभ अवश्य मिलेगा। छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगम सहित, नगर पालिका, नगर पंचायत एवं त्रि स्तरीय पंचायतों में भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता प्राप्त होगी। त्रि स्तरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव के लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार है। मोदी जी की गारंटी के अधिकांश वादों को पूरा करने के कारण प्रदेश भर में भाजपा के प्रति विश्वास का वातावरण है।इसी विश्वास की बदौलत हमें इस चुनाव में भी ऐतिहासिक जनादेश मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में चुन-चुन कर कर्मठ एवं योग्य ऊर्जावान प्रत्याशियों को उतारा है। मीनल जी भी अनुभवी और योग्य नेत्री हैं। मीनल चौबे एक बेहतर महापौर रायपुर के लिए साबित होंगी। पंचायत से पार्लियामेंट तक भाजपा प्रत्याशी बड़ी संख्या में चुन कर आयेंगे।सभी प्रत्याशियों को फिर से शुभकामनाएं हैं।

ढेबर ने विकास के नाम पर लूट मचाई थी: गुप्ता

बूढ़ातालाब सौंदर्यीकरण में 36 करोड़ सहित स्मार्ट सिटी के कार्यों भारी भ्रष्टचार हुआ

राजधानी में जो भी विकास कार्य हुए हैं, वह भाजपा सरकारों की देन

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदारानाथ गुप्ता ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लुटेरे और भ्रष्टाचारी कांग्रेसी ठगेश के और वो उनके हैं। कांग्रेसियों को लेकर एक आम धारणा बन गई कि कांग्रेसी सम्मान जाय पर लूट-खसोट और भ्रष्टाचार की रीति व नीति न जाए, वाली राह पर चलते हैं। ये कांग्रेसी चाहे कोई भी चुनाव हो, ये वेश बदलकर जनता के बीच उनके हितैषी बनकर जाते हैं। लेकिन जनता का वोट लेकर सत्ता पाते ही ये अपने लूट तंत्र में लग जाते हैं। इतना ही नहीं वे जनता को लूटने के काम में अपने भाई-भतीजा और बेटों तक को लगा देते ।इसी नक्शे-कदम पर कांग्रेस के पूर्ववर्ती रायपुर मेयर एजाज ढेबर भी पूरे पांच साल में शहर के विकास के नाम पर भ्रष्टाचार के अनेक आरोप लगते रहे हैं

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री गुप्ता कहा कि एजाज ढेबर को रायपुर नगर निगम में भ्रष्टाचार करने के लिए ठगेश ने मेयर पद के सीधे जनता द्वारा चुनाव को पार्षदों के माध्यम से कराने का कानून बना दिया था। जिसे साय सरकार ने फिर जनता द्वारा प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का निर्णय लिया तो कांग्रेस ने एजाज को मेयर का टिकट नहीं दिया, क्योकि ठगेश और कांग्रेस को पता है कि मेयर रहते एजाज ढेबर के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोपो से जनता में आक्रोश है। जिसे कांग्रेस भली-भांति जानती है, इसलिए इस बार ढेबर को मेयर का टिकट नहीं देकर, पूर्व मेयर प्रमोद दुबे की पत्नी को टिकट देकर कांग्रेस के परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ धोखा दिया है। जबकि कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी के पति भी अपने पूर्व कार्यकाल में ठगेश गिरोह के साथ मिलकर अपने लोगों को ठेके देने के अलावा कोई काम नहीं किया है। उन्होंने निकाय चुनाव में जनता को आगाह करते हुए कहा है कि बंटोगे तो फिर इन कांग्रेसियों के द्वारा लुटोगे। क्योंकि भ्रष्टाचार कांग्रेसियों के खून में है। कांग्रेस ने इस बार भी 70 पार्षद प्रत्यशियों को मैदान में तो उतारा है, जो जीतने के बाद सिर्फ विकास के नाम पर लूट मचाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने पैसे देकर पार्षद का टिकट पाया। इसलिए जनता ने इस बार ठाना है कि इन्हें हराकर शहर में भाजपा के सुशासन को लाकर विकास लाना है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने पूर्व महापौर ने अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में न तो शहर का समुचित विकास किया और न ही जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवा पाए। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने कहा 2019-2024 के दौरान केंद्र सरकार ने रायपुर नगर निगम को 1254 करोड़ रुपये से अधिक की फंडिंग दी। इसमें सफाई के लिए 74 करोड़ रुपये और पेयजल योजनाओं के लिए करोड़ों रुपये शामिल थे। इसके बावजूद जनता को पानी और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल सकीं। उन्होंने बूढ़ा तालाब सौंदर्यीकरण के नाम पर 36 करोड़ रुपए, गोल बाजार और जवाहर बाजार परियोजनाओं में महापौर गंभीर भ्रष्टाचार किए हैं। उन्होंने कहा कि करोड़ों की लागत से बने फव्वारे प्रारंभ से ही बंद पड़े हैं। मल्टीलेवल पार्किंग और उद्यानों का व्यवसायीकरण कर जनता के हितों की अनदेखी की गई। इस काम में मेयर एजाज ढेबर ने अपने कांग्रेसी पार्षदों के साथ जमकर लूट मचाई थी। इस बार कांग्रेस की लूट और भ्रष्टचार से ऊब चुकी जनता कांग्रेस का रायपुर ही नहीं पूरे प्रदेश के नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में सूपड़ा साफ कर देगी और भाजपा के सुशासन पर मुहर लगाएगी।

भाजपा की विजय सुनिश्चित करने मैदान में उतरे सांसद बृजमोहन

रायपुर। रायपुर सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने भाजपा की विजय सुनिश्चित करने के लिए नगरीय निकाय चुनाव में पूरे जोश और समर्पण के साथ मोर्चा संभाल लिया है। मंगलवार को नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन उन्होंने राजधानी रायपुर और महासमुंद में भाजपा प्रत्याशियों की नामांकन रैलियों में भाग लेकर कार्यकर्ताओं और जनता का उत्साहवर्धन किया।

श्री अग्रवाल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने पहले विधानसभा और फिर लोकसभा चुनावों में कमल खिलाकर भाजपा पर जो विश्वास जताया है, वही विश्वास राज्य में तेज विकास का आधार बना है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अगुवाई और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्ग दर्शन में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के कारण गरीबों को प्रधानमंत्री आवास, महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत ?1000 की राशि, किसानों को ?3100 प्रति क्विंटल धान खरीदी, स्वास्थ्य तथा अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अब समय आ गया है कि एक बार फिर नगर निगम में कमल खिलाकर अपने गली-मोहल्लों को सुंदर और विकसित बनाएं।

उन्होंने कहा कि भाजपा की प्राथमिकता जनसेवा और विकास है। नगरीय निकायों में भाजपा की विजय सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ता पूरी प्रतिबद्धता से जुटे हैं। श्री अग्रवाल ने जनता से अपील की कि वे भाजपा प्रत्याशियों को अपना समर्थन दें ताकि राज्य का सर्वांगीण विकास जारी रह सके। इस अवसर पर मंत्री श्री राम विचार नेताम, विधायक श्री राजेश मूणत, विधायक श्री सुनील सोनी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे। नामांकन रैलियों में उमड़ा जनसैलाब यह संकेत दे रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को जनता का भरपूर समर्थन मिलेगा। महासमुंद में नगर पालिका अध्यक्ष पद के भाजपा प्रत्याशी डॉ. विमल चौपड़ा जी, रायपुर से महापौर उम्मीदवार श्रीमती मीनल चौबे और पार्षद प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया।रायपुर नगर निगम चुनाव के संचालक बने सांसद बृजमोहनबता दें कि, सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल की राजनीतिक समझ, अनुभव और संगठनात्मक क्षमता को देखते हुए उन्हें रायपुर नगर निगम चुनाव का संचालक बनाया गया है। यह उनकी रणनीतिक क्षमता और जनता के बीच उनकी पकड़ को दर्शाता है।

राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त हेमबती का राजभवन में सम्मान

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा संचालित बालगृह (बालिका) कोंडागांव में निवासरत बालिका जूडो खिलाड़ी कुमारी हेमबती को 26 दिसम्बर को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया था। उन्हें मेडल और प्रमाण पत्र पुरस्कार की राशि रु 1 लाख रुपए प्रदान किया गया था।छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद के संयुक्त सचिव राजेन्द्र कुमार निगम ने बताया कि 29 जनवरी को राज्यपाल रमेन डेका ने भी राजभवन में आयोजित %एक भारत श्रेष्ठ भारत% राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हेमबती को स्मृति चिन्ह और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया। हेमबती को पद्मश्री मदन चौहान और ऊषा बारले ने भी बधाई व शुभकामनाएं प्रेषित की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद के संयुक्त सचिव राजेन्द्र कुमार निगम, बालगृह कोंडागांव से अधीक्षक मणि शर्मा, प्रतिमा मिश्रा, गजेन्द्र पटेल के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, केरल , उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

डॉ. अरविन्द नेरल को चिकित्सा शिक्षक का लाईफ टाईम अचीवमेंट अवार्ड

रायपुर। पं.ज.ने. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में गणतंत्र दिवस पर आयोजित सम्मान समारोह में छत्तीसगढ़ राज्य के वरिष्ठतम चिकित्सा शिक्षक डॉ. अरविन्द नेरल को चिकित्सा शिक्षा व सेवाओं के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए लाईफ टाईम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉ. अरविन्द नेरल ने विगत 41 वर्षों से सतत् चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और फ़ॉरेंसिक मेडिसीन विषयों में शिक्षक और विभागाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दी है। डॉ. विवेक चौधरी, अधिष्ठाता के कार्यकाल में महाविद्यालय के इतिहास में पहली बार चिकित्सा शिक्षकों, तकनीकी, लिपिकीय, नर्सिंग व चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।

वंचित पात्र किसानों को मिलेगा एक और टोकन, आदेश जारी

रायपुर। शासन द्वारा निर्धारित टोकनों में किसी कारणवश अपना धान नहीं बेच पाने वाले किसानों को अपना बचत धान बेचने एक और अतिरिक्त टोकन मिलेगा । शासन द्वारा नीतिगत निर्णय लेने अधिकृत खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव अन्बलगन पी ने आज बुधवार को इस आशय का आदेश जारी कर दिया है । धान खरीदी की निर्धारित तिथि समाप्त होने के कगार पर पहुंचने के बाद भी इस संबंध में आदेश जारी नहीं होने से ऐसे किसानों में आक्रोश व्याप्त था व वे लगातार शासन - प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कर रहे थे ।बीते कल ही मुख्यमंत्री विष्णु देव साय , मुख्य सचिव अमिताभ जैन व मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह को मेल से ज्ञापन भेज ध्यानाकर्षण कराने वाले किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेंद्र शर्मा ने बतलाया है कि श्री अन्बलगन ने प्रदेश के सभी जिलाधीशों को जारी परिपत्र में टोकन एवं रकबा समर्पण संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिये विभिन्न जिलों से आवेदन मिले हैं । इसके परिपेक्ष्य में बीते 25 जनवरी तक पंजीकृत किसानों से प्राप्त टोकन एवं रकबा समर्पण संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु प्राप्त आवेदन का समुचित परीक्षण कर धान क्रय करने हेतु खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी माड्यूल के जरिये एक अतिरिक्त टोकन जारी कर सकता है इसके साथ ही त्रुटिपूर्ण रकबा समर्पण होने पर रकबा को पुनः रिस्टोर कर पात्रतानुसार धान लिया जा सकता है ।

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

कृषि विश्वविद्यालय का दशम् दीक्षांत समारोह 1 फरवरी को

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर का दशम् दीक्षांत समारोह कल 1 फरवरी, 2025 को आयोजित किया जाएगा। कृषि महाविद्यालय रायपुर स्थित कृषि मंडपम में प्रातः 11 बजे से आयोजित इस दीक्षांत समारोह में लगभग 4 हजार 191 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएगी। दीक्षांत समारोह राज्यपाल एवं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति रमेन डेका की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एण्ड बायोटेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉ. वांगा शिवा रेड्डी दीक्षांत उद्बोधन देंगे। कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल विद्यार्थियों को दीक्षोपदेश देंगे। दीक्षांत समारोह के दौरान मेधावी विद्यार्थियों को 16 स्वर्ण, 18 रजत एवं 24 कांस्य पदक प्रदान किये जाएंगे। इस दौरान भव्य दीक्षांत शोभायात्रा भी निकाली जाएगी।दीक्षांत समारोह में शैक्षणिक वर्ष 2022-23 एवं 2023-2024 में कृषि विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को पदक एवं उपाधियाँ वितरित की जाएँगी। दीक्षांत समारोह में बी.एस.सी. कृषि पाठ्यक्रम के 2 हजार 841, बी.एस.सी. उद्यानिकी पाठ्यक्रम के 17, बी.टेक. कृषि अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम के 303 तथा खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के 20 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी।

गलतबयानी कर रहे हैं डिप्टी सीएम साव: शुक्ला

रायपुर। डिप्टी सीएम अरुण साव के पत्रकार वार्ता पर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि अपनी ही पार्टी के जनाधार वाले नेता और कार्यकर्ताओं के हक का गला घोटना, लिफाफा संस्कृति से प्रत्याशी तय करना ही भाजपा का राजनीतिक चरित्र है, अरुण साव अपनी पार्टी की चिंता करे। जगदलपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के भतीजे सहित दर्जनों कार्यकर्ता, खैरागढ़ जिला उपाध्यक्ष, छुई खदान महिला मोर्चा मंत्री, बीजापुर, सुकमा, रायगढ़ सहित पूरे प्रदेश में भाजपा के जमीनी कार्यकर्ताओं की व्यथा सर्व विदित है। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि चिरमिरी में भाजपा ने महापौर का टिकट जिसे बेचा है उसने पिछला चुनाव पार्टी के खिलाफ़ लड़ा था और कुल 4 वोट पाए थे, भाजपा कार्यकर्ताओं का इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है? कार्यकर्ता पार्टी की रीड होते हैं, उन्हें गुलाम और पैडवर्कर समझना भाजपा नेताओं की भूल है, भाजपा के कार्यकर्ता आने वाले चुनाव में इन्हें सबक सिखाएंगे। किसी की पत्नी होना किसी भी तरह से अयोग्यता नहीं है, यह भाजपा की महिला विरोधी सोच का प्रमाण है। भाजपा की वर्तमान महापौर प्रत्याशी भी जब पहली बार पार्षद चुनाव लड़ी थी।

समझौता यापार और उद्योगों को नई दिशा देगा: पारवानी

रायपुर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव,राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि कल दिनांक 28 जनवरी 2025 को छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और आईआईटी भिलाई इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन के मध्य (एमओयू) समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ। आईआईटी भिलाई और छत्तीसगढ़ चेंबर का ऐतिहासिक समझौता राज्य के व्यापार और उद्योगों को नई दिशा देगा।चेंबर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में व्यापार, उद्योग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने तथा व्यापार और नवाचार के नविन अवसरों को खोजने छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और आईआईटी भिलाई इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन के मध्य ऐतिहासिक (एमओयू) समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। पारवानी ने बताया कि चेंबर की ओर से चेंबर पदाधिकारियों में प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, प्रदेश महामंत्री अजय भसीन, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मनमोहन अग्रवाल, संजय चौबे एवं आईआईटी भिलाई के डायरेक्टर राजीव प्रकाश, आईआईटी भिलाई इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन के सीईओ प्रशांत माथुर, विष्णु वैभव द्विवेदी, संतोष विश्वास जी ने हस्ताक्षर किए।

महापौर पद हेतु 109 अभ्यर्थियों ने भरा नामांकन

रायपुर, 29 जनवरी 2025 / नगर पालिका आम निर्वाचन 2025 अंतर्गत राज्य के 10 निगमो के महापौर पद हेतु कुल 109 अभ्यर्थियों ने नामांकन जमा किया। इसी तरह नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद हेतु कुल 816 अभ्यर्थियों ने तथा सभी नगरीय निकायों के पार्षद पद हेतु कुल दस हज़ार 776 अभ्यर्थियों ने निर्धारित तिथि 28 जनवरी तक नामांकन दाखिल किया। नगरपालिका आम निर्वाचन 2025 अंतर्गत राज्य के 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका परिषद एवं 114 नगर पंचायतों के लिए आम निर्वाचन होना है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा गत 20 जनवरी को निर्वाचन की तारीखों की घोषणा की गई थी। 22 जनवरी को निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई और 28 जनवरी 2025 दिन मंगलवार तक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। अभ्यर्थियों से नाम वापस 31 जनवरी तक ली जा सकती है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना, प्रकाशन करना और निर्वाचन प्रतिकों का आबंटन के लिए भी 31 जनवरी 2025 की तिथि निर्धारित की गई है। 11 फरवरी को मतदान तथा 15 फरवरी को मतगणना एवं निर्वाचन परिणामों की घोषणा की जायेगी। 10 नगरपालिक निगम में जगदलपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, अंबिकापुर एवं चिरमिरी शामिल है।

महापौर पद के लिए 28 उम्मीदवारों ने भरा नामांकन

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन था. रायपुर नगर निगम के महापौर पद के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया. इस बार महापौर पद के लिए राजनीतिक दलों और निर्दलीय कुल 28 उम्मीदवारों ने नामांकन फॉर्मभरा है.महापौर पद के लिए आम आदमी पार्टी से डॉ. शुभांगी अंजू चंद्रशेखर तिवारी, भारतीय जनता पार्टी से मीनल चौबे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से दीप्ति प्रमोद दुबे, बहुजन समाज पार्टी से डॉ. सितारा खान, शिवसेना से अनीता कुलदीप, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी से चांदनी साहू, शिवसेना (यू.बी.टी.) से ज्योति सिंह, धूं सेना से मीना तिवारी (अधिवक्ता), गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से प्रिया शर्मा, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी से ऋचा वर्मा, शक्ति सेना (भारत देश) से सविता शैलेन्द्र बंजारे और निर्दलीय में डॉ. आरती रामेश्वर सोनवानी, गायत्री सिंह, मोबिना खान, नंदिनी नायक, नूसरत बेगम, राधेश्वरी गायकवाड़, रूबीना बेगम, सरिफुन निशा, सरोज बेन सोलंकी, सायरा बेगम, शबिस्ता खान, शगुप्ता अंजुम खान, शोभा, शोभा यादव, सुषमा आनंद अग्रवाल, तहमीना परवीन, तलत उन्नीशा शामिल हैं.छत्तीसगढ़ में 20 जनवरी से आचार संहिता लागू हो गई है. नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 22 जनवरी से 28 जनवरी तक चलेगी. नाम वापसी की अंतिम तिथि 31 जनवरी है. नगरीय निकाय चुनाव की वोटिंग 11 फरवरी को होगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग की कार्यशाला में शामिल हुए राज्यपाल

विवि में अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित करें : राज्यपाल

रायपुर । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक-आर्थिक समूहों के बीच शैक्षिक अंतर को पाटना है। लचीली डिग्री संरचनाओं और बहुविषयक शिक्षण मार्गो से विद्यार्थियों को अधिक अनुकूलित शिक्षा प्रदान की जा सकती है। विश्वविद्यालयों में अनुसंस्थान गतिविधियों को प्रोत्साहित करने से ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

राज्यपाल रमेन डेका ने बुधवार को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में आयोजित कार्यशाला में उक्ताशय के विचार व्यक्त किए।उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए एक रोडमैप विषय पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला के प्रथम दिन राज्यपाल डेका मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

डेका ने अपने उद्बोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ में मार्च 2024 से एनईपी 2020 को लागू करना शुरू कर दिया गया है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। शिक्षा व्यक्तियों को आधुनिक कार्य बल के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करती है, आर्थिक विकास और नवाचार को बढ़ावा देती है। उच्च शिक्षा संस्थान अनुसंधान और विकास, नवाचार को बढ़ावा देने, विकसित राज्य और विकसित भारत प्राप्त करने के लिए युवाओं के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल का पोषण और प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।उन्होंने कहा कि शिक्षा जनसंख्या को आवश्यक कौशल, ज्ञान और महत्वपूर्ण सोच क्षमता प्रदान करके इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे उन्हें अर्थव्यवस्था और समाज में सार्थक योगदान करने में सक्षम बनाया जा सके।डेका ने कहा कि नई शिक्षा नीति (एनईपी) समग्र विकास को बढ़ावा देने, प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने और क्षेत्रीय असमानताओं को संबोधित करके भारत की शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने के महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती है। लेकिन योग्य शिक्षकों की कमी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, राज्यों में असंगत कार्यान्वयन जैसी कुछ चुनौतियां भी है। अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण भी आवश्यकता है। प्रशिक्षित शिक्षक द्वारा दी गई शिक्षा विद्यार्थियों के जीवन को दूर तक प्रभावित करती है। प्रशिक्षण और नवाचार जीवन के सभी क्षेत्रों में आवश्यक है। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि 21 वीं सदी के लिए जो चुनौतियां है उसे विज्ञान की मदद से दूर किया जा सकता है।उन्होंने कहा कि एनईपी शिक्षा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण पर जोर देता है।

ईवीएम के बारे में मतदाताओं की जिज्ञासाओं को शांत करने हर वार्ड में लगेगी प्रदर्शनी

रायपुर। नगरीय निकाय चुनाव में इस बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा. ईवीएम को लेकर मतदाताओं में मन में तमाम जिज्ञासाओं को शांत करने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निकाय क्षेत्र के हर वार्ड में प्रदर्शन और जानकारी केंद्र बनाने के साथ नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा. जानकारी के अनुसार, प्रत्येक प्रदर्शन केन्द्र में मास्टर ट्रेनर की ड्यूटी लगाई जाएगी, जो ईवीएम के संचालन एवं मतदान प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी आम नागरिकों को डिमोंस्ट्रेट करके बताएंगे, साथ ही उनकी शंकाओं का निराकरण करेंगे.

नाम वापसी की तिथि से मतदान के दो दिवस पूर्व तक ईवीएम का प्रदर्शन किया जाए, जिसमें डमी मतपत्र प्रयोग किया जाएगा. डमी मतपत्र में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या समान हो सकती है, लेकिन निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम एवं प्रतीक डमी मतपत्र में मुद्रित नहीं होंगे. इसके अलावा प्रत्येक जिले में चुनाव नियम और ईवीएम डेमो के लिए मीडिया वर्कशॉप का भी आयोजन किया जाएगा.

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.